नंदिनी खंडेलवाल: नमस्कार। भारतीय वैश्विक परिषद में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की पैनल चर्चा का विषय है- अफ्रीका को नया आकार देती जेन ज़ी (Z)-नीत डिज़िटल विचारः स्वरूप और प्रभाव। इससे पहले की हम आगे बढ़ें, मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर डाल लें। धन्यवाद। आज की चर्चा में, हमें यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे साथ इस सत्र के अध्यक्ष राजदूत राजीव भाटिया, दक्षिण अफ्रीका और केन्या के पूर्व उच्चायुक्त है और ये आज की कार्यवाही का संचालन भी करेंगे।

आज हमारे साथ पांच विशिष्ट वक्ता भी जुड़े हैं। इनमें से दो जाने- माने विशेषज्ञ भी हैं। हमारे पैनल के पहले सदस्य हैं मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के एसोसिएट फेलो डॉ. अभिषेक मिश्रा, इसके बाद पर्यवेक्षक अनुसंधान फाउंडेशन के एसोसिएट फेलो डॉ. समीर भट्टाचार्य अपने विचार हम सब के साथ साझा करेंगें। हमारे पैनल के साथ वर्चुअल माध्यम से कोफ़ी अन्नान अंतरराष्ट्रीय शांतिरक्षा प्रशिक्षण केंद्र, घाना के डॉ. गॉडफ्रेड बोनाह नकानसाह जुड़ेंगें। चर्चाकर्ता के रूप में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की वरिष्ठ अध्येता डॉ. रुचिता बेरी और भारतीय वैश्विक परिषद की शोध निदेशक डॉ. निवेदिता रे भी शामिल हैं।

आज हमारे साथ एक और पैनल सदस्य, युगांडा से प्रोफेसर डॉ. सोलोमन विनी ऑनलाइन जुड़नेवाले थे। हालाँकि आज युगांडा में आम चुनाव हैं इसलिए दुर्भाग्य से पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। फिर भी, उन्होंने हमें अपना पहले से रिकॉर्ड किया हुआ सेशन भेजा है। अध्यक्ष महोदय के संचालन में सत्र के आखिरी हिस्से में प्रश्नोत्तर सत्र के साथ आज की चर्चा का समापन होगा।

इसके साथ ही मैं राजदूत राजीव भाटिया से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना शुरुआती भाषण दें और आज की कार्यवाही में हमारा मार्गदर्शन करें।

राजीव भाटिया: बहुत- बहुत धन्यवाद, नंदिनी। निवेदिता, एक बार फिर आपके और आपकी टीम का साथ पा कर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आईसीडब्ल्यूए की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सम्मेलन कक्ष उम्मीद रखने वालों से भरा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा पैनल उनकी उम्मीदों पर खड़ा होगा। आज का विषय नए साल की शुरुआत के लिए बहुत ही उचित विषय है, अफ्रीका में जेन ज़ी (Z) के विरोध आंदोलन, विशेषरूप से डिजिटल विचार अफ्रीका को बहुत ही निष्पक्ष तरीके से नया आकार दे रही हैं और फिर इसका स्वरूप और प्रभाव। लेकिन बातचीत को दिलचस्प बनाने के लिए, हम वास्तव में इस बात पर फोकस करने वाले हैं कि अफ्रीका में यह पीढ़ी किस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से क्या करने की कोशिश कर रही है, जिन पर पूरे महाद्वीप में ध्यान दिया जा रहा है।

उम्र के हिसाब से मैं शायद जेन ज़ी (Z) से बहुत दूर हूँ इसलिए यह उचित होगा कि मैं अपने हालिया शोध के आधार पर कुछ बातें आप सभी से साझा करूँ। लेकिन, यदि मुझे जानकारी नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैं कक्ष में मौजूद सभी युवाओं से पूछूंगा कि वे बताएं कि असल में हो क्या रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर जेन ज़ी (Z) को उन लोगों के रूप में परिभाषित करता है जो असल में 14 से 29 वर्ष की उम्र के हैं। मुझे लगता है कि यहाँ कोई भी 20 वर्ष से कम उम्र का नहीं है लेकिन कुछ लोग शायद उम्र की इस सीमारेखा पर हों। निश्चित रूप से इस कक्ष में शायद 50% या उससे भी अधिक जेन ज़ी (Z) के लोग हैं। उन्हें तरह- तरह के नाम दिए गए हैं, कुछ लोग उन्हें डिजिटल नेटिव कहते हैं तो कुछ लोग उन्हें ज़ूमर्स कहते हैं।

यह सहस्राब्दि पीढ़ी और अल्फा पीढ़ी के बीच पैदा हुए लोगों का समूह है और वे इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए हैं। ध्यान रखें, यह सोशल मीडिया आंटी- अंकल टाइप का फेसबुक नहीं है। यह ज्यातर टिककॉक (TikTok) और निश्चित रूप से एक्स (X) और इंस्टाग्राम (Instagram) है। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना होगा कि इस पीढ़ी की विशेषता क्या है

और अब हम नतीजे देख रहे हैं। हम जो देख रहे हैं, वह असल में अफ्रीका के अलग- अलग हिस्सों में होने वाली गतिविधियों की एक पूरी श्रृंखला है।

यह बताया गया कि, हालांकि एक तरह से यह नाइजीरिया, घाना, केन्या जैसे दूसरे देशों में पहले शुरू हुआ था लेकिन बीते दो वर्षों- '25 से '26 की अवधि में, मेरे द्वारा बनाई गई देशों की सूची में शामिल देशों से इतर दूसरे देशों पर अधिक रहा। और वे मेडागास्कर, मोरक्को, टोगो जैसे देशों की ओर भी इशारा करते हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें एक साथ जोड़ रही है? क्या यह केवल एक विशेष अफ्रीकी घटना है? मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। असल में यह ग्लोबल साउथ की घटना है। जैसा कि हम जानते हैं, यह हमारे आस-पास दक्षिण एशिया में भी हो रहा है। हमने यह सब नेपाल में एक धीमी फिल्म की तरह शुरू होते देखा है।

कुछ मायनों में, बिल्कुल वैसा तो नहीं, लेकिन कुछ मायनों में बांग्लादेश और श्रीलंका में भी ऐसा ही देखा गया है। लेकिन नेपाल एक विशेष उदाहरण था, जहाँ जैसे ही सोशल मीडिया का एक्सेस बंद किया गया, युवा पीढ़ी ने विद्रोह कर दिया और देखते- ही- देखते इतनी तेज़ी से कार्रवाई हुई कि सरकार गिर गई। हमें कुछ तो अंदाज़ा है ही। लेकिन दूसरे देश भी हैं- इंडोनेशिया, फिलीपींस, पेरू, पैराग्वे, तिमोर-लेस्ते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह ग्लोबल साउथ की घटना है। लेकिन आज हम मुख्य रूप से अफ्रीका पर बात करेंगे।

मैं आईसीडब्ल्यूए और उसके शोधार्थियों को बहुत ही अच्छा अवधारणा नोट तैयार करने के लिए बधाई देता हूँ। मैं अवधारणा नोट का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ क्योंकि यदि अवधारणा नोट सही है तो चर्चा भी शायद सही दिशा में आगे बढ़ेगी। बेशक हम सब जानते हैं कि सम्मेलन कक्ष में आने से पहले कोई भी वास्तव में अवधारणा नोट्स को नहीं पढ़ता। इसलिए यदि आपने इसे पढ़ा है तो आप पहले से ही अन्य प्रतिभागियों से आगे हैं। इस विशेष सम्मेलन के लिए बनाए गए अवधारणा नोट्स का मुख्य मुद्दा यह है कि इसमें देशों के नाम बताए गए हैं और कुछ बुनियादी विशेषताएं बताई गई हैं और सही सवाल उठाए गए हैं।

मुझे लगता है, जैसा कि हम सब जानते हैं, पीएचडी विद्यार्थी, जब आप अपने मूलभूत सवाल पूछते हैं तो आपके लिए थीसिस लिखना बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ जो मूल सवाल है, और मैं अब वास्तव में अपने पैनल के सदस्यों से बात कर रहा हूँ, वह यह है कि हमने अफ्रीका में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्षों के बारे में सुना है। तो पहला सवाल यह है कि क्या इन विरोध प्रदर्शनों का अफ्रीका के महान नेताओं जैसे न्क्रूमा, नासिर और मंडेला के नेतृत्व में हुए वर्ग संघर्षों से कोई लेना- देना है।

एक और सवाल है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्या हम केवल विरोध आंदोलनों पर बात कर रहे हैं या अफ्रीका में शासन के बड़े दायरे पर बात कर रहे हैं। वास्तव में, हम शासन के सवाल पर बात कर रहे हैं क्योंकि यह शासन तकनीक, अर्थव्यवस्था, शहरीकरण के रुझानों और सबसे बढ़कर जनसांख्यिकीय लाभांश से प्रभावित होती है। इस बुनियादी नोट में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आज अफ्रीका में 70% लोग 30 वर्ष से कम उम्र के हैं।

तो वास्तव में यह एक युवा महाद्वीप है। हम भारत के लिए भी ऐसे ही आंकड़ों की बात करते रहते हैं और अक्सर हम दूसरों के बारे में नहीं सुनते लेकिन यह एक ऐसा उदाहरण है जहाँ अफ्रीका, आज के 1.4 अरब लोग और 2050 में ये बढ़कर 2.5 अरब हो जाएंगे, सच में बहुत युवा हैं। इसलिए केवल वही लोग हैरान होंगे जिन्होंने यह नहीं समझा कि अफ्रीका में जेन ज़ी(Z) आंदोलन जारी है।

एक और बात जो मैं बताना चाहूँगा, वह यह है कि करीब 10 वर्ष पहले दक्षिण अफ्रीका के बड़े विचार मंच- इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़ ने अफ्रीका का भविष्य-केंद्रित शोध किया था और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नतीजा निकाला था कि अफ्रीका में लोकतंत्र के प्रति एक प्रकार का रुझान है और उन्होंने दावा किया था कि 2035 तक, वे 2015 में अपनी बात लिख रहे थे और उन्होंने कहा था कि 20 साल के बाद, अफ्रीका के और अधिक देशों में लोकतंत्र होगा और अधिक तरक्की होगी और अधिक स्थिरता होगी। यह 20 वर्षों के लिए उनका अनुमान था।

लेकिन 10 साल के बाद ही हम जो देख रहे हैं, वह यह है कि स्थिति कुछ कमज़ोर हुई है। लोकतंत्र तो है। मुझे लगता है कि तब भी आईएसएस (ISS) ने दावा किया था कि उस समय अफ्रीका की 38% आबादी लोकतंत्र में थी और 60% से अधिक लोग किसी-न- किसी प्रकार के अर्ध-लोकतंत्र में थे। लेकिन अब हमने बीते दो वर्षों '24 और '25 में देखा कि सैन्य तख्तापलट हो रहे हैं, लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है। शायद यह भी बताता है कि हम अब जेन ज़ी(Z) की प्रतिक्रिया पर अधिक ध्यान क्यों दे रहे हैं। ज़ाहिर है, शायद, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि क्या हम उनके बारे में कुछ निश्चित फैसला करने की स्थिति में हैं या हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि यह सब हमें कहाँ ले कर जाता है।

मेरी आखिरी बात, मुझे लगता है कि भारत में हमारे लिए अफ्रीका को बेहतर तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है और हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। यदि आप एक सप्ताह तक दक्षिण एशिया के बारे में शीर्ष चार अंग्रेजी राष्ट्रीय अखबार पढ़ते हैं, तो आप खुद को दक्षिण एशियाई विषयों का एक महान विशेषज्ञ बता सकते हैं। लेकिन अफ्रीका के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में आपको अफ्रीका के बारे में कुछ भी पढ़ने नहीं मिलेगा। आपको सच में बहुत मेहनत करनी होगी, कुछ भी मतलब की बात लिखने के लिए आपको अफ्रीका के बारे में जानकारी ढूंढ़नी होगी। तो यह वह चुनौती है जिसका सामना हमारे अफ्रीकी विशेषज्ञ करते हैं लेकिन हमें उनका जीवन थोड़ा आसान बनाने का तरीका ढूंढ़ना होगा क्योंकि सच कहूं तो यदि हम अफ्रीका को नहीं समझते तो हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।

तो दोस्तों, मैंने आपके सामने कुछ आपस में जुड़े विचार रखें हैं। मुझे उम्मीद है कि ये पैनल के सदस्यों के लिए काफी सोचने पर मज़बूर करने वाले होंगे और अब मैं मुझे दिए गए कार्यक्रम का अनुपालन करते हुए अपने साथी, आईडीएसए के बहुत ही होनहार अफ्रीकी विशेषज्ञ डॉ. अभिषेक मिश्रा से अनुरोध करूँगा, आपको अपनी समय- सीमा आदि तो पता ही है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने विचार हम सभी से साझा करें, अभिषेक आपकी बारी।

अभिषेक मिश्रा: चलिए, सबसे पहले आज मैं आप सभी को अफ्रीका में जो हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं। मुझे लगता है कि 1950 के दशक के आखिर और 1960 के दशक की शुरुआत में जब अफ्रीकी देशों को ब्रिटिश और फ्रांसीसी शासन से आज़ादी मिलनी शुरू हुई, तो इससे अफ्रीकी महाद्वीप पर नए लोकतंत्र के भविष्य को लेकर बहुत सारी उम्मीदें पैदा हुईं। बहुत उम्मीद थी कि नए चुने होंगे, नव लोकतांत्रिक देश अपने देश की बागडोर खुद संभाल पाएंगे और नियमित रूप से स्वतंत्र, निष्पक्ष, आम चुनाव करवा पाएंगे जो वास्तव में आम अफ्रीकी लोगों की सच्ची सोच को दिखाएंगे।

लेकिन अफसोस, हुआ वह जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। महाद्वीप में नागरिक अशांति और अराजकता फैल गई और कई अफ्रीकी देशों के तथाकथित राष्ट्र निर्माता स्वयं को कानून से ऊपर समझने लगे। नतीजतन, अपनी सत्ता बनाए रखने के प्रयास में, उन्होंने चुनाव में हेरफेर और हिंसा की एक बहुत ही जटिल व्यवस्था शुरू कर दी। बाद में पूरे महाद्वीप में ऐसा ही होने लगा।

तो चुनावों में हेराफेरी वाली व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि पुराने नेता बने रहे, जिससे यह संस्कृति बन गई, एक ऐसी संस्कृति जिसमें अफ्रीकी युवाओं को राजनीति में सक्रिए हिस्सेदारी से मनाही है। अफ्रीका में वर्तमान नेतृत्व भी, यह व्यवस्था अफ्रीका में

वर्तमान नेतृत्व को दर्शाता है, जहाँ अधिकतर वर्तमान नेतृत्व 70 से 79 वर्ष और 80 से 89 वर्ष के नेताओं के हाथ में है। दरअसल मैं यह कह रहा हूँ कि उनका नेतृत्व वृद्ध है।

बूढ़े नेताओं की बात करें तो, कई उदाहरण हैं, जैसे कैमरून के पॉल बिया या भूमध्यरेखीय गिनी के टियोडोर ओबियांग, कोटे डी आइवर के अलासाने औटारा, और ज़िम्बाब्वे के एमर्सन म्नांगाग्वा, युगांडा के योवेरी मुसेवेनी, सूची बहुत लंबी है। ज़ाहिर है, इनमें युवा नेता भी हैं। लेकिन विडंबना यह है कि अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे अधिक युवा आबादी होने के बावजूद, यह आज भी ज्यादातर वृद्धों द्वारा संचालित है। इसका सीधा- सीधा मतलब है कि एक ऐसा देश या समाज जिस पर वृद्ध शासन करते हैं।

अब, जेन ज़ी (Z) के नेतृत्व वाली क्रांति, या इसे विरोध कह लें, मेरे कहने का मतलब है, बेशक, बहुत ज्यादा चुनावी लामबंदी हुई है, लोकतंत्र समर्थन नारे लगे हैं, विरोध प्रदर्शन हुए हैं। युवा डिजिटल रूप से बहुत अधिक सक्रिए हो रहे हैं, आदि। सूडान, केन्या से कई उदाहरण हैं विशेष रूप से हैशटैग रूटो मस्ट गो या रिजेक्ट फाइनेंस बिल, यहाँ तक कि अडाणी समूह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी। तो इस महाद्वीप में युवाओं की सक्रियता स्पष्ट नज़र आती है। उत्तरी अफ्रीका में भी, अरब स्प्रिंग की विरासत, ट्यूनिशिया और मिस्र में देशों, लोगों, युवाओं को विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर रही है।

लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वह इस तथाकथित उद्धारकर्ता राजनीति से काफी अलग है। उद्धारकर्ता राजनीति से मेरा मतलब है कि युवा एक करिश्माई या राजनेता की तलाश करेंगे जो समाज की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए काम करेगा। यह व्यवस्था अधिक विकेंद्रिकृत व्यवस्था की तरफ, अधिक मुद्दा- आधारित जवाबदेही की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए चुने हुए नेताओं को ठोस नतीजे देने में नाकाम माना जा रहा है जिसकी वजह से अफ्रीकी युवा स्मार्टफोन, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स, डिस्कार्ड सर्वर आदि के माध्यम से डिजिटल टूल्स का प्रयोग करने पर विवश हो रहे हैं।

लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अफ्रीका में चुनाव केवल मतदान केंद्रों पर ही नहीं लड़े जाते। उत्तरोत्तर, अफ्रीकी चुनावों का नतीजा डिजिटल स्पेस पर सामने आ रही कहानियों, गलत जानकारी और दुष्प्रचार से निर्धारित होता है, और यह प्रवृत्ति बढ़ ही रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शक्ति, गति और पहुँच से इसे और बढ़ावा मिलता है। लेकिन गलत जानकारी, दुष्प्रचार केवल अफ्रीकी घटना नहीं है। विश्व भर में हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं कि कैसे गलत जानकारी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर किया है और वास्तव में सरकार और नागरिकों के बीच की खाई को बढ़ा दिया है।

तो असल में, हमारे पास जो बचता, वह है राज्य और नागरिक के बीच सामाजिक अनुबंध का टूटना। यही एक वजह है कि इस महाद्वीप के कुछ हिस्सों में इतने सारे तख्तापलट भी हो रहे हैं। तो हितधारकों और आम लोगों के बीच जो विश्वास होना चाहिए, वह पूरी तरह से गायब है और जिसका नतीजा यह होता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कमज़ोर होती हैं। वास्तव में, लोकतंत्र के काम करने के लिए सरकारी संस्थानों पर विश्वास बहुत ज़रूरी है। यह लोकतंत्र के ठीक से काम करने के लिए अनिवार्य है।

लेकिन असल में, सरकारी संस्थानों पर विश्वास कम होता जा रहा है। एफ्रैबैरोमीटर, जो बहुत सारे सर्वेक्षण करता है, उसने हाल ही में 2021 के आखिर से 2023 के बीच, 39 अफ्रीकी देशों में लगभग 58,000 लोगों पर सर्वे किया। उनके सर्वेक्षण के नतीजों में पाया गया कि महत्वपूर्ण संस्थानों पर अफ्रीकी लोगों का विश्वास कम हुआ है। एक दशक पहले के स्तर की तुलना में यह कम हो रहा है। केवल धार्मिक नेताओं पर विश्वास या सेना पर विश्वास या परंपरागत नेताओं पर ही विश्वास बढ़ा है। लेकिन राष्ट्रपति, या न्यायालय या संसद, पुलिस जैसे राजनीतिक संस्थानों पर अफ्रीकी लोगों पर विश्वास चिंताजनक रूप से कम हो रहा है।

भौगोलिक रूप से भी, यह अलग है। मेरे कहने का अर्थ है, पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका में, तंजानिया जैसे पूर्वी देशों में या नाइज़र, बुर्किना फासो जैसे पश्चिमी अफ्रीकी देशों में विश्वास बहुत अधिक है, जबकि मध्य, दक्षिणी या उत्तर अफ्रीका के देशों में इन सभी

सरकारी संस्थानों पर विश्वास कम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि स्थिति किसी भी प्रकार के युवा आंदोलन के लिए, स्पष्ट रूप से, जेन ज़ी (Z) के नेतृत्व वाले डिजिटल आंदोलन से कोई भी सार्थक नतीजा निकलने के लिए, मुझे लगता है कि हम अफ्रीकी देशों को या अफ्रीकी युवाओं को, या विश्व के जिस भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उन्हें अधिकारियों के साथ केवल टकराव पर फोकस करने की बजाय युवाओं की अधिक सक्रिए भागीदारी पर ध्यान देना होगा, जैसा कि हम देख रहे हैं।

लेकिन साथ ही, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि किसी भी सत्तावादी या सैन्य सरकार के अधीन लोकतंत्र काम नहीं करता क्योंकि सेना के अधीन, सैन्य सरकारें वास्तव में किसी भी प्रकार की लोकतांत्रिक नैतिकता, सिद्धांतों या मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ होती हैं। अपनी बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

राजीव भाटिया: बहुत- बहुत धन्यवाद, अभिषेक। निर्धारित समय में अपनी प्रस्तुति पूरी करने और बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण तथ्य साझा करने के लिए। मुझे लगता है कि आपने राजनीतिक पहलुओं पर ध्यान दिया और यह भी बताया कि अफ्रीकी संस्थानों पर विश्वास, शायद चर्च जैसे एक या दो को छोड़कर, कम हो रहा है। मुझे लगता है कि आपने गंभीर राजनीति में परिवर्तन के बारे में भी बहुत अच्छी बातें कहीं। मेरे ख्याल से यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके प्रशोधन का बहुत- बहुत धन्यवाद।

अब हम एक अन्य होनहार और अफ्रीकी मामलों के विशेषज्ञ डॉ. समीर भट्टाचार्य का रुख करेंगे। मैं उन्हें बहुत समय से जानता हूँ इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लगभग सात- आठ मिनटों में अपने विचार हमसे साझा करें।

समीर भट्टाचार्य: अध्यक्ष महोदय, बहुत- बहुत धन्यवाद। आईसीडब्ल्यूए में वापस आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज के आमंत्रण के लिए धन्यवाद। मुझे यहां बहुत सारे जाने- पहचाने और पुराने दोस्त, शिक्षक दिख रहे हैं। मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से अध्यक्ष महोदय ने परिचय दिया था। मैंने वास्तव में अवधारणा नोट्स पढ़े हैं। मैं अवधारणा नोट के आधार पर बात करूँगा। मेरे दोस्त अभिषेक ने पहले ही विरोध प्रदर्शन, शासन संबंधी चुनौतियों के बारे में बात कर ली है। वर्ष 2020 में, पूरे विश्व में बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए थे।

जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा, यह ग्लोबल साउथ की बात है। शायद यह 2022 में, श्रीलंका से शुरू हुआ। फिर 2024 में, हमने बांग्लादेश में देखा, हमने नेपाल में भी ऐसा ही कुछ देखा। लेकिन 2025 में, पूरे अफ्रीका में, यह जून में टोगो में शुरू हुआ। फिर यह केन्या में हुआ। अगले महीने यह केन्या में हुआ। फिर यह मोरक्को में हुआ। फिर यह मेडागास्कर में हुआ। यदि आप भौगोलिक दायरा, भाषा, संस्कृति के लिहाज से देखें तो यह बहुत अलग है। इसमें आम क्या है? इन सभी विरोध प्रदर्शनों में एक बात आम थी, इनकी अगुवाई युवाओं ने, जिन्हें हम जेन ज़ी (Z) कहते हैं, ने की। इस जेन ज़ी (Z) को कुछ लोग जेनरेशन एंग्जायटी भी कहते हैं।

ये वैसे लोग हैं जिनमें सहनशीलता की बहुत कमी है। वे वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हैं। वे परिवर्तन चाहते हैं और तुरंत चाहते हैं। ये वैसे लोग हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है लेकिन क्या यह पहली बार है जब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? नहीं, पहले भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, मेरे कहने का अर्थ है, केवल अरब स्प्रिंग ही नहीं, बीते 10 वर्षों में, यदि आप अरब स्प्रिंग के विरोध प्रदर्शन देखें तो इन लोगों ने तकनीक की मदद ली है। विरोध प्रदर्शन हुए हैं, अध्यक्ष महोदय ने क्वामे न्क्रूमा के बारे में बताया है। अध्यक्ष महोदय ने जूलियस न्येरेरे के बारे में भी बताया। ये वे लोग थे जिन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया था। लेकिन उस समय, उन्हें तकनीक का सहयोग नहीं था।

वर्तमान समय का विरोध प्रदर्शन, ये युवा जो विरोध कर रहे हैं, यह बहुत ज़रूरी है, आपको यह समझना होगा कि यह सबसे अधिक तकनीक वाली पीढ़ी है। इस पीढ़ी से पहले किसी भी पीढ़ी को यह मौका नहीं मिला था कि जन्म लेने के पांच वर्ष की उम्र

होते- होते मोबाइल फोन प्रयोग करने की सहूलियत हो। हमें भी यह मौका नहीं मिला था। ये वैसे लोग हैं जो पहले से ही कनेक्टेड हैं। फिर, सोशल मीडिया ने बहुत मदद की है। किस तरह? सबसे पहले, सोशल मीडिया ने जानकारी साझा करने में मदद की। यदि मेरे साथ कुछ हो रहा है तो तकनीक के बिना मैं इसे कैसे साझा कर सकता हूँ? लेकिन जब मैं इसे साझा करता हूँ तो यह एक सामूहिक आवाज़ बन जाती है। यह पहली बात है।

दूसरी बात, अलग- अलग देशों में अनुभव को साझा करने में भी तकनीक बहुत मदद करती है। इसलिए लोग सीख सकते हैं। जैसे, एक केन्याई देख सकता है कि मोरक्को में क्या चल रहा है? अच्छा, हमें भी इसी तरह करना चाहिए। नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। इसलिए लोगों द्वारा सीमापार से सीखने के भी मामले हैं। फिर, तीसरी महत्वपूर्ण बात, निश्चित रूप से, सरकार लगातार इंटरनेट पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है, जैसा कि हमने सुना है कि युगांडा में आज भी इंटरनेट नहीं है। लेकिन फिर ये जेन ज़ी (Z) बहुत ही होशियाह हैं। वे वीपीएन (VPN) का इस्तेमाल करते हैं। वे सरकार को बेवकूफ बना सकते हैं। उनके पास इस तरह की सुविधाएं भी हैं।

अब केवल अफ्रीका की बात करते हैं, 2025 में जेन ज़ी (Z)-नीत विरोध प्रदर्शन हुए, वे कितने सफल रहे? तो चलिए शुरू करते हैं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सफलता जो मिली, वह मेडागास्कर में थी, क्योंकि वे सरकार बदलने में कामयाब रहे थे। लेकिन यदि आप देखें तो यह जेन ज़ी (Z) नहीं थे जिन्होंने सरकार बदली। आखिरकार सेना को दखल देना पड़ा और सेना ने ही सरकार बदली। केन्या का उदाहरण ले लीजिए, केन्या में क्या हुआ, शुरुआती विरोध वित्त बिल के खिलाफ था। सरकार ने कहा, ठीक है, हम वित्त बिल वापस ले रहे हैं लेकिन वे अभी भी वित्त बिल में बदलाव की प्रक्रिया में हैं। जल्द ही, वित्त बिल आएगा, शायद कुछ छोटे- मोटे बदलावों के साथ। लेकिन आएगा ज़रूर।

और आज भी, हर दूसरे दिन की तरह, केन्या से एक विरोधकर्ता गायब हो रहा है। विरोध करने वाले गायब किए जा रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वहां हुए प्रदर्शन कितने सफल हैं। फिर आप मोरक्को आएं। मोरक्को में क्या हुआ? विरोध प्रदर्शन क्यों हुए? शुरुआती विरोध प्रदर्शन मैटरनिटी वार्ड में छह महिलाओं की मौत के कारण हुए। यहाँ एक मुद्दा स्वास्थ्य का है। शिक्षा एक और मुद्दा है क्योंकि रोज़गार नहीं है। स्नातक किए युवाओं, पीएचडी किए युवाओं के लिए भी कोई नौकरी नहीं है। इसलिए उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए विरोध प्रदर्शन किया।

अब मोरक्को में संसदीय राजतंत्र है। राजा ने कहा, अच्छी बात है, हम शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान देंगे। लेकिन कुछ नहीं किया गया। इसलिए मेरे ख्याल से विरोध प्रदर्शन सफल रहे। कम- से- कम लोगों ने आवाज़ उठाया। सरकार ने जाना की ज़मीनी स्तर पर क्या चल रहा है। लेकिन यदि आप सच में ज़मीनी नतीजे देखें, तो मुझे नहीं लगता कि इसने वह हासिल किया जो यह करना चाहता था। अब इसमें क्या कमियां थीं? इसने वह क्यों हासिल नहीं किया जो इसे करना था?

एक वजह यह होनी चाहिए कि, जैसा कि आपने बताया, अध्यक्ष महोदय ने नेताओं के बारे में बताया। इन विरोध प्रदर्शनों का एक लाभ यह है कि ये कायिक (ऑर्गेनिक) हैं। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन कायिक परिस्थिति की समस्या यह है कि उनका कोई नेता नहीं होता। इसलिए विरोध प्रदर्शन तो हो रहा है लेकिन उन्हें नहीं पता कि आखिर लक्ष्य क्या है। विरोध प्रदर्शन के बाद, असल में क्या चाहते हैं? तो ये चुनौतियाँ हैं। अब, मुझे लगता है कि आपने आईएसएस (ISS) रिपोर्ट के बारे में बात की। तो मैं भी पढ़ रहा था कि अफ्रीका में भविष्य कैसा होगा। ब्लूमबर्ग ने एक पब्लिकेशन निकाला है जिसमें कहा गया है कि 2026 विरोध प्रदर्शनों का एक और साल होने वाला है। उन्होंने कुछ देशों जैसे इथियोपिया, सीएआर (CAR) और डीआरसी (DRC) के बारे में भविष्यवाणी की है। ये तीन देश हैं जो सार्वजनिक छात्र विरोध प्रदर्शन या जेन ज़ी(Z) विरोध प्रदर्शन की कगार पर हैं।

आने वाले समय में हम देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन अभिषेक ने इस गलत जानकारी फैलाने वाले अभियान के बारे में बात की है। एल्गोरिद्म भी एक ऐसी चीज़ है जो इन जेन ज़ी(Z) प्रदर्शकारियों के खिलाफ काम करती है। एल्गोरिद्म से आप अलग-अलग चीज़ें दिखा सकता हैं। तो यह 2026 कैसा होगा, हम देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि केवल सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने से अंतिम लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता। धन्यवाद।

राजीव भाटिया: बहुत- बहुत धन्यवाद, समीर। आपने जो कहा, उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। मुझे लगता है कि आप जिस प्रकार से भौगोलिक प्रसार पर ध्यान दे रहे हैं, वह बहुत आवश्यक है। मुझे खुशी है कि आप अफ्रीका को बड़ी ग्लोबल साउथ कहानी का हिस्सा मान रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जेन ज़ी(Z) ने लोगों के सामने अपनी नाराज़गी रखने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन ये डिजिटल विरोध केवल कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं है। लोग वास्तव में सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने सुरक्षा बलों से लड़ाई की है। उन्हें मारा गया है, घायल किया गया है और गिरफ्तार भी किया गया है।

लेकिन जब आप सड़कों पर आकर देश की परंपरागत सत्ता का सामना करते हैं तो आपको पता चलता है कि ज़िंदगी अपने कंप्यूटर के बटन दबाने या मोबाइल का प्रयोग करने से कहीं अधिक मुश्किल है। असल ज़िंदगी में बहुत बड़ा फर्क होता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के हमारे समय से बहुत पहले, हम जानते हैं कि जो लोग बाद में नेता बने, उन्होंने अंग्रेजों से अपनी पीठ पर लाठियां खाईं। यह केवल स्मार्टफोन से नहीं हुआ था। बहुत फर्क है। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन अच्छी बात है लेकिन इसमें बलिदान देना होगा। बहुत लंबा संघर्ष करना होगा। इसमें संगठन और प्रबंधन की आवश्यकता होगी। हमें देखना होगा कि यह कैसे होता है। यह अफ्रीका में एक नई घटना की केवल शुरुआत हो सकती है।

हम अभी इसे शुरुआती चरण में देख रहे हैं लेकिन यह बताने के लिए आपका बहुत- बहुत धन्यवाद, विशेषरूप से आपकी शोध के अनुसार 2026 तनाव और उथल- पुथल का एक और साल हो सकता है, यह बात कुछ सोचने पर मज़बूर करती है क्योंकि हम सभी अंतरराष्ट्रीय संबंधों यानी आईआर(IR) के छात्र यहाँ बैठे हुए जानते हैं कि विश्व पहले से ही भू-राजनीति में उथल- पुथल भरे वर्ष के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। इसलिए, आपने जिस नज़र से अभी अफ्रीका के बारे में बताया, उससे हम सब थोड़े और सजग हो गए हैं। बहुत- बहुत धन्यवाद, अब हमारे साथ डॉ. गॉडफ्रेड बोनाह नकानसाह हैं और मुझे लगता है कि हम उन्हें डिजिटल माध्यम से सुन पाएंगे, वास्तव में यह बहुत अच्छा है। मैं विशेष रूप से आपका बहुत स्वागत करता हूँ। हमें माफ़ करें, आज चर्चा कर रहे हम भारतीयों में से ज्यादातर लोग शायद ही कभी अफ्रीका महाद्वीप गए हों लेकिन बात ऐसे करते हैं जैसे कि हम अफ्रीका को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप पहले अफ्रीकी वक्ता हैं जिन्हें हम आज सुनेंगे और मैं आपके विचारों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके विचारों को बहुत गंभीरता से सुना जाएगा। सर, अपनी प्रस्तुति आरंभ करें।

गॉडफ्रेड बोनाह नकानसाह: बहुत- बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय और पैनल के सदस्यों को मेरा अभिवादन। मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत- बहुत धन्यवाद। मैं अफ्रीका के जनसांख्यिकीय संदर्भ और आर्थिक कारकों के बीच संबंधों पर अपने विचार आप सबके बीच रखूंगा और वे किस प्रकार जेन ज़ी(Z) के राजनीतिक रवैये को प्रभावित कर रहे हैं या जेन ज़ी(Z) के राजनीतिक रवैये को आकार दे रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि अफ्रीका का जनसांख्यिकीय संदर्भ ही बुनियाद है, जो हमें इस महाद्वीप पर हो रहे सभी राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों के बारे में जानकारी देता है।

तो हाँ, 30 बरस से कम उम्र के 70% अफ्रीकी हैं और इस बात पर आज सुबह हमारी चर्चा में बहुत ज़ोर दिया गया है, लेकिन मैं इसे औसत उम्र के नज़रिए से देखना चाहता हूँ। जब हम अफ्रीका की औसत उम्र को देखते हैं तो यह 19 वर्ष से भी कम है। तो आधे अफ्रीकी 19 वर्ष से कम उम्र के हैं और यह सामाजिक-आर्थिक रूप से बड़ी चुनौतियां पेश करता है। इसलिए, इस महाद्वीप की जनसांख्यिकीय संरचना ने अफ्रीकी सरकारों के लिए आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करना बहुत मुश्किल बना दिया है क्योंकि

अधिकांश अफ्रीकी उत्पादकता की उम्र में नहीं हैं, वे 19 वर्ष से कम उम्र के हैं, जिसका मतलब है कि वे स्कूल में हैं, वे उपभोक्ता हैं, वे अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं कर रहे हैं।

हम राजनीतिक जनसांख्यिकी से जानते हैं कि किसी भी देश को उम्र की संरचना के आधार पर जनसांख्यिकीय लाभांश पाने के लिए, उस देश की औसत उम्र 25.6 वर्ष और 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए, 25.6 वर्ष और 42 वर्ष के बीच। इससे देश को अपने कामकाजी वर्ग से अधिक- से- अधिक लाभ उठाने का मौका मिलता है। हमारे पास अफ्रीका का उदाहरण है, जहाँ औसत उम्र 19 वर्ष से कम है। इसलिए मेरे हिसाब से अफ्रीका की आर्थिक चुनौतियां आने वाले कई दशकों तक जारी रहने की संभावना है जब तक कि आबादी की उम्र का ढांचा मौलिक रूप से बदल नहीं जाता और अधिकांश अफ्रीकी औसत उम्र के दायरे में नहीं आ जाते, जिससे उत्पादकता बढ़ सके।

इसका असर बड़े हो रहे युवा अफ्रीकियों के लिए आर्थिक अवसरों पर पड़ा है, विशेषरूप से जेन ज़ी(Z) पीढ़ी पर। मुझे लगता है कि इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि भले ही विश्व बैंक के आंकड़ों में इस महाद्वीप में युवाओं में बेरोज़गारी की दर अधिक है लेकिन यह औपचारिक क्षेत्र के लिए है। अधिकांश युवा अफ्रीकी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में हैं। इसलिए वे कुछ- न- कुछ कर रहे हैं, लेकिन औपचारिक व्यवस्था के तहत नहीं, जिसका मतलब है कि सबसे बड़ी चुनौती युवाओं की बेरोज़गारी या काम न करना नहीं है, बल्कि ज्यादातर अफ्रीकियों के लिए रोज़ी- रोटी की अनिश्चितता या स्थायी रोज़गार की कमी है।

अफ्रीकी युवाओं के पास करने के लिए कुछ काम तो है लेकिन वो लंबे समय तक चलने वाला काम नहीं है। इससे सरकारों पर औपचारिक क्षेत्र का विस्तार करने का बहुत अधिक दबाव है ताकि अफ्रीकियों की उस बड़ी, अधिक पढ़ी-लिखी पीढ़ी को रोज़गार मिल सके जो अभी हमारे पास है। इसने कई अफ्रीकी युवाओं को राजनीतिक या डिज़िटल सक्रियता को बढ़ावा दिया है। लेकिन पूरे महाद्वीप में जो हो रहा है, उसका दिलचस्प हिस्सा यह है कि जेन ज़ी(Z) की शिकायतें केवल आर्थिक नहीं है, वे केवल अपनी आर्थिक असुरक्षा को दूर करने के बारे में नहीं है।

दिलचस्प बात यह है कि हमने इस महाद्वीप में जिन मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन होते देखे हैं, वे कई क्षेत्रों से जुड़े हैं। जैसे, यदि आप घाना को लें, तो हाल के महीनों में, जेन ज़ी(Z) के प्रदर्शनों का फोकस पर्यावरणीय स्थिरता पर रहा है। यह अवैध खनन के खिलाफ था। भले ही आर्थिक चुनौतियां हैं, लेकिन कई युवा अफ्रीकियों के बीच पर्यावरण संबंधी चिंताएं, भविष्य के मुद्दों और वर्तमान मुद्दों के रूप में ज़ोरदार तरीके से सामने आई हैं, जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको ये बारीकियां देखने को मिलती हैं।

जब आप नाइज़ीरिया का उदाहरण लेते हैं, तो एंड एसएआरएस (End SARS) विरोध प्रदर्शन मूल रूप से आर्थिक वज़हों से नहीं था। यह देश में पुलिस की बर्बरता और सुरक्षा की कमी का मामला था। इसलिए सुरक्षा का संदर्भ भी जेन ज़ी(Z) के विरोध प्रदर्शनों में, डिजिटल और ऑफलाइन दोनों तरह से, प्रमुखता से सामने आता है। फिर जब आप साहेल पर नज़र डालते हैं तो बुर्किना फासो, माली, नाइज़र जैसे देश, वहाँ जेन ज़ी(Z) द्वारा डिजिटल सक्रियता का फोकस मुख्य रूप से उनकी सरकारों की फ्रांसीसी साम्राज्यवादी प्रभाव को समाप्त करने में असमर्थता पर रहा है।

वे अफ्रीका की आज़ादी के बाद की राजनीति को दिखाते हैं। इसलिए अलग- अलग देशों में, सरोकार अलग- अलग दिखते हैं। फिर जब आप टोगो का मामला लेते हैं, तो वह राजनीतिक था और यह उसके खिलाफ था जिसे विशेषज्ञ आमतौर पर सरकार द्वारा संवैधानिक हेरफेर कह देते हैं। जेन ज़ी(Z) अपने राजनीतिक कार्यों में, ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों प्रकार से बहुत सुनियोजित हो रहे हैं। हाँ, आर्थिक मुद्दे तो हैं ही, जैसा कि हमने केन्या के मामले में वित्त बिल में देखा, लेकिन वे पर्यावरण के मुद्दों में भी दिलचस्पी रखते हैं। उन्हें सुरक्षा के मुद्दों में भी दिलचस्पी है। उन्हें राजनीतिक मुद्दों में भी दिलचस्पी है। और इसने इस महाद्वीप

में या कई मोर्चों पर डिजिटल सक्रियता के लिए जगह बनाई है जो इस महाद्वीप के युवाओं की दिलचस्पी और जुनून पर आधारित है।

मुझे लगा कि यह बताना आवश्यक है कि आर्थिक कारण ही एकमात्र कारण नहीं है। कुछ और भी मुद्दे हैं जो उतने ही ज़रूरी है जिन पर जेन ज़ी(Z) के लोग प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इस पर भी अपने विचार देने हैं कि अभी रचनात्मक स्थिति के लिए युवा सहभागिता हेतु कौन से मॉडल उपलब्ध हैं जो विश्वास को फिर से बनाते हैं और संभावित रूप से डिजिटल सक्रियता को विवाद में बदलने से रोकते हैं। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद के दौर में या आज़ादी के दौर की कहानियों से आगे, अफ्रीकी सरकारों को इस बात को समझना होगा कि जैसा कि हमारे सम्मानित अध्यक्ष महोदय ने सही कहा था, यह पीढ़ि डिजिटल रूप से समझदार युवाओं की पीढ़ी है। वे ऑनलाइन रहते हैं और ऑनलाइन ही सोशलाइज़ यानि सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं।

मुझे लगता है कि अफ्रीकी सरकारें अभी भी बहुत सख्त हैं और ज्यादातर युवाओं के साथ संपर्क स्थापित करने में परंपरागत तरीकों पर ही विचार करती हैं। लेकिन आपको संसद में युवा सरकारों के साथ संबंध स्थापित करते नहीं मिलेंगे। आपको वे राजनीतिक पार्टियों में सक्रिए रूप से शामिल होते हुए नहीं मिलेंगे। वे ऑनलाइन हैं और इसका मतलब है कि देश और युवाओं के बीच संबंध स्थापित करने के तरीके परंपरागत स्थानों से बदलकर ऑनलाइन स्थानों पर जाने चाहिए, जहाँ वास्तव में युवा उपस्थित हैं। हालांकि, हम देखते हैं कि कई अफ्रीकी देशों में, युवाओं का ऑनलाइन जुड़ना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है।

हमने वर्तमान में युगांडा में यही देखा है। चुनाव हो रहे हैं और इंटरनेट बंद है। क्यों? क्योंकि सरकार ने ऑनलाइन युवाओं की भागीदारी को सुरक्षित कर दिया है। यह ज़रूरी है कि हम उस सोच से बाहर निकलें और युवाओं द्वारा सार्वजनिक संलग्नता के लिए वैकल्पिक स्थान के रूप में डिजिटल सक्रियता (एक्टिविज्म) को अपनाएं। सरकारों को डिजिटल स्पेस और डिजिटल संवाद को पुरानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पूरक संलग्नता स्थान के रूप में देखने के इस विचार को वास्तव में अपना लिया है। मुझे लगता है कि यह सोच बहुत ज़रूरी है।

वर्तमान में, उन्हें सरकार के हितों के खिलाफ माना जाता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है। आखिर में, समय की कमी के कारण, मुझे लगता है कि डॉ. अभिषेक ने सार्थक युवा भागीदारी की बात की थी। यह बहुत आवश्यक है। इसलिए क्योंकि हम शासन में युवाओं का केवल सांकेतिक प्रतिनिधित्व देखते हैं। हमें सत्ता में युवाओं का उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिख रहा है। इसलिए युवा अभी भी स्वयं को हाशिए पर महसूस करते हैं और डिजिटल स्पेस को ऐसी जगह मानते हैं जहाँ वे अपने हितों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने अपने पिछले वक्ता से जाना, ऑनलाइन जुड़ाव के परिणाम वास्तव में बहुत अच्छे रहे हैं।

यदि आपका विरोध प्रदर्शन किसी नागरिक सरकार को गिरा देता है उसके स्थान पर सैन्य सरकार आ जाती है तो उसे सफल नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह ज़रूरी है कि यह कोशिश शासन में युवाओं की सार्थक भागीदारी या प्रतिनिधित्व पर भी ध्यान दे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आने वाले समय में हम इस विषय और चर्चा करेंगे। बहुत- बहुत धन्यवाद।

राजीव भाटिया: धन्यवाद, डॉ. गॉडफ्रेड नकान्सा। कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें साझा करने के लिए धन्यवाद। हमें आपसे इससे कम की उम्मीद नहीं थी क्योंकि आप उसी देश में हैं और आप न केवल घाना का नज़रिया, बल्कि विशेष रूप से महत्वपूर्ण अफ्रीकी नज़रिया ले कर आए। मुझे लगता है कि आपने मूल रूप से यह कहा कि इस डिजिटल सक्रियता के पीछे केवल आर्थिक कारण ज़िम्मेदार नहीं है, इसे भी ध्यान में रखना होगा। आपने हमारे लिए एक बिल्कुल नए शब्द का भी प्रयोग किया, डिजिटल ऑप्टिमिज़्म- जो ज़िंदगी के प्रति अफ्रीकी नज़रिए की बहुत ही खास बात है। मुझे भी यह बात समझ आ गई।

मुझे आशा थी कि आप कुछ क्षेत्रीय विविधता पर भी बात करेंगें, यह विरोध आंदोलन पूर्वी अफ्रीका और द्वीप देश मेडागास्कर या उत्तर अफ्रीकी देश मोरक्को में किस तरह से अलग है लेकिन हम उस पर बाद में आएंगे। मैं अभी आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। हम युगांडा के एक विद्वान, जैसा कि नंदिनी ने पहले बताया, प्रोफेसर डॉ. सोलोमन विनी की रिकॉर्ड की हुई प्रस्तुति देखने का प्रयास करेंगे। क्या हम उनका पहले से रिकॉर्ड की हुई प्रस्तुति को देख सकते हैं?

सोलोमन विनी: पैनल के माननीय सदस्यों, दर्शकों और प्रतिभागियों, नमस्कार। मेरा नाम डॉ. सोलोमन विनी है। मैं मेकरेरे यूनिवर्सिटी में व्याख्याता हूँ और आज मैं अफ्रीका में राजनीतिक स्थिति और जेन ज़ी(Z) के नेतृत्व वाले डिजिटल विरोध के उदय के बारे में बात करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, युगांडा में इंटरनेट की सुविधा नहीं है इसलिए मेरे पास यह पूर्व में रिकॉर्ड किया गया वीडियो है, मैंने जैसे - तैसे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की व्यवस्था की थी।

थोड़ी पृष्ठभूमि बताता चलूं, अफ्रीका में औसत उम्र लगभग 19 वर्ष है और इससे पता चलता है कि राजनीति युवा-नीत होती जा रही है और ये जेन ज़ी(Z) अपनी बात कहने वाले, स्थानीय, नेटवर्क वाले और निश्चित रूप से केंद्रीत हैं। हम देखते हैं कि विरोध की राजीति पार्टी-नीत से विमुख हो रही है, अब वे परंपरागत राजनीतिक पार्टियां नहीं रहीं बल्कि वे ह्वाट्सऐप (WhatsApp), फेसबुक (Facebook), टिकटॉक (TikTok) और निश्चित रूप से एक्स (X), जो पहले ट्विटर था, जैसे प्लेटफॉर्म बन गए हैं। दावा, बेशक, युगांडा में छोटे होते क्षेत्रें या नागर राज्यों का चौराहा है लेकिन हम जो देखते हैं वह ज्यादातर आर्थिक अस्थिरता और नेटवर्क वाली डिजिटल संस्कृति है।

युगांडा में बेशक, यह डिजिटल तरीके से युवाओं को एकजुट करने के महाद्वीपय पैटर्न का हिस्सा है लेकिन यह युगांडा की चुनाव-केंद्रित और सुरक्षा- प्रधान राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित है, जिसे हम चुनाव के समय देखते हैं, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं। अहम बात यह है कि ये आंदोलन केवल कुछ समय का असंतोष नहीं है बल्कि ये अफ्रीका में राजनीतिक भागीदारी की संरचनात्मक परिवर्तन का संकेत देते हैं। युगांडा का राजनीतिक माहौल कैसा है और इसे कौन सा माहौल समर्थन दे रहा है?

हम एक बहुत ही नियंत्रित राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं जिसे डिजिटल रूप से संबंधित पीढ़ी की आवश्यकता है। बेशक, हम लंबे समय तक सत्ता में रहने और केंद्रित कार्यकारी अधिकारी देखते हैं, हम केंद्रित चुनाव और नागिरक मीडिया स्पेस का कम होना देखते हैं लेकिन बेरोज़गारी, असमानता और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियां भी हैं जो इन युवाओं को विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए मज़बूर करती हैं। लेकिन जेन ज़ी(Z) को लगता है कि औपचारिक राजनीतिक चैनल कोई जवाब नहीं देते, इसी वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हुई हैं।

लेकिन नतीजा, हम देखते हैं कि राजनीति संस्थानों से प्लेटफॉर्म पर आ गयी है। विरोध भी राजनीतिक रैलियों की बजाए सोशल मीडिया फीड्स, हैशटैग और टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड समूहों पर आ गया है। हम जो देख सकते हैं वह है युगांडा के लोगों और शेष अफ्रीका के लोगों की अलग- अलग कहानी। हमारे लिए, हमारे पास लीड, लाइट, नेटवर्क मोबिलाइज़ेशन है और बेशक, इसे दोहराना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हम बड़े और तेज़ तरीकों पर निर्भरता देखते हैं, जो विरोध प्रदर्शनों की पुलिसिंग की वजह से हैं। हम देखते हैं, जैसे अभी, युवाओं ने अलग- अलग तरीकों से वीपीएन (VPN) पर स्विच करने की कोशिश की है, और निश्चित रूप से प्रवासियों का प्रसार भी एक वजह है।

यह सब मुद्दा- आधारित शिकायतों से लेकर व्यवस्थित आलोचना तक तेज़ी से बढ़ने की कोशिश है। लेकिन हम एक मज़बूत चुनावी प्रक्रिया भी देखते हैं जिसमें हमें विरोध प्रदर्शनों को नियमित चुनौती के रूप में पाते हैं। लेकिन हम जो देख पा रहे हैं वह यह है कि बड़े विरोध प्रदर्शन नागरिक अभिव्यक्ति के रूप में कम और सुरक्षा जोखिम के रूप में अधिक होते हैं। अफ्रीकी परिदृश्य के बारे में क्या? और मैं चाहता हूँ कि हम इस महाद्वीप के जेन ज़ी(Z) विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में युगांडा को देखें क्योंकि हमने

इसे केन्या, नाइज़ीरिया, सेनेगल, सूडान में देखा है लेकिन उन सभी में कुछ बातें आम हैं, जैसे आर्थिक कारण, कर, रहने का खर्च और रोज़गार। हैशटैग द स्ट्रीट। हमने ऐसे रास्ते देखे हैं जो विकेंद्रित हैं, युवा नीत हैं और पार्टियों पर विश्वास नहीं रखते।

हमने इन विरोध प्रदर्शनों को अधिकांश रूप से नौतिक जवाबदेही के रूप में देखा है, न कि विचारधारा के रूप में। हमने इसे सबूतों वाली राजनीति के रूप में देखा है, जहाँ वीडियो, लाइवस्ट्रीम, सिटीजन जर्नलिज़्म हैं, इन सबने विशेष नीतियों की बजाय वैधता को उजागर करने के लिए पीढ़ीगत चुनौती खड़ी की है। अरब स्प्रिंग की तुलना में नया क्या है? निश्चित रूप से समानता यह है कि ये अभी भी न्यूज़ आधारित, तकनीक- समर्थित प्लेटफॉर्म हैं जो निश्चित रूप से आर्थिक और सम्मान से संबंधित शिकायतों से शुरू हुए हैं। लेकिन नया स्पेस, जो हम देखते हैं, वह ज्यादातर डिजिटल पारितंत्र है जो अब एल्गोरिद्म पर निर्भर करता है और निश्चित रूप से, उन पर नज़र रखी जाती है और वे बंटे हुए भी हैं।

लेकिन हम देख रहे हैं कि राष्ट्रों ने दमन करना सीख लिया है। आप इससे कैसे निपटेंगे? पहले, हमने युगांडा में इंटरनेट बंद करवा दिया लेकिन अब कुछ खास इलाके हैं जहाँ हम जानबूझकर शटडाउन करते हैं। निश्चित रूप से डिजिटल धमकियाँ भी मिल रही हैं। इसलिए, राष्ट्र इन मुद्दों को निपटाने के तरीके के मामले में बदल गए हैं। बेशक, सरकार के जल्द गिरने का कोई भ्रम नहीं है। हम यह भी पाते हैं कि विरोध प्रदर्शन अक्सर धीमे होते हैं, लेकिन लगातार होते हैं और क्रांतिकारी नहीं होते। तो इस बहस का नतीजा क्या है?

यह अरब स्प्रिंग नहीं है। यह मुख्य रूप से तनाव का का लंबा नेटवर्क है। लोकतंत्र और राजनीतिक विश्वास का क्या अर्थ है? हम जो देख पा रहे हैं, वह निश्चित रूप से जेन ज़ी(Z) और डिजिटल राजनीति है लेकिन वे संस्थानों पर बहुत कम विश्वास करते हैं। केवल मतदान को काफी नहीं माना जाता, इसलिए हमें मतदाता उदासीनता देखने को मिलती है। विरोध प्रदर्शन एक समानांतर जवाबदेही तंत्र बन गए हैं। लेकिन, बेशक, दमन अलगाव को बढ़ाता है और डिजिटल प्रतिरोध को मजबूत करता है।

तो जोखिम क्या है? मुझे लगता है कि खतरा यह है कि यदि आप इस खाई को नहीं पाटते तो हमें विरोध प्रदर्शनों में कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही सेना का कट्टरपंथी होना और आप सब भी सुन रहे हैं, जिसे सत्तावादी व्यवस्था की बातें कहा जाता है। यही परिणाम होने की संभावना है। लेकिन हमें यह भी जानना होगा कि क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है। जो चीज़ काम नहीं करती वह है इंटरनेट शटडाउन्स। यह काम नहीं करती। विरोध प्रदर्शनों को अपराध मानना, बिना सुधार के सहयोग, जेन ज़ी(Z) को सुरक्षा समस्या के रूप में देखना। वास्तव में यह सरकारों और युवाओं, जो आबादी का एक बड़ी हिस्सा हैं, के बीच बड़ी खाई पैदा कर रहा है।

क्या काम करता है? मेरे हिसाब से, जो चीज़ काम करती है वह है विश्वसनीय आर्थिक समावेश की राह, शायद हम डिजिटल नागरिक संवाद के स्थानों के बारे में विचार कर सकते हैं, हमारे पास युवाओं के प्रति संवेदनशील शासन सुधार कार्यक्रम भी हो सकते हैं और आखिर में, आईए क्षेत्रीय नियमों पर विचार करें जैसे दक्षिण अफ्रीकी समुदाय, एसएडीसीसी (SADCC), ईसीएएस (ECAS और (ध्वनि स्पष्ट नहीं है/ Inaudible), या उस स्तर पर अफ्रीकी संघ जैसे क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय के माध्यम से डिजिटल स्थानों या नागरिक स्थानों की सुरक्षा करना।

तो मेरी प्रस्तुति का अंतिम परिणाम यह है कि युगांडा में युवाओं के विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं हैं, वे इसकी अनुकूलन क्षमता के लिए एक तनाव परीक्षा है। मुझे सुनने के लिए बहुत- बहुत धन्यवाद। पहले से रिकॉर्ड कर अपनी प्रस्तुति आप सभी से साझा करने के लिए आप सब मुझे माफ करें लेकिन आप सब जानते ही हैं कि युगांडा में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। धन्यवाद।

राजीव भाटिया: बहुत- बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि दूसरी तरफ से, यानी पूर्वी तरफ से, यह नज़रिया राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन विभाग के एक युवा ने व्याख्यान दिया, जो कंपाला की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी, मकरारे यूनिवर्सिटी से हैं। मुझे लगता है कि हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि यह डिजिटल सक्रियता, डिजिटल अभिव्यक्तियां, युगांडा उन शुरुआती देशों में से एक था जहाँ यह सब शुरू हुआ, और वास्तव में यह एक सीमा तक सफल भी हुआ क्योंकि उस समय सरकार ने की गई कई मांगों पर रियायतें दीं और अब मुझे नहीं मालूम कि इसका और अभी के चुनावों में क्या संबंध है और क्या होगा लेकिन हमें उस देश से भी एक अच्छा गंभीर नज़रिया मिला है।

आईसीडब्ल्यूए (ICWA) का धन्यवाद कि उसने पूरब और पश्चिम दोनों को कवर किया, लेकिन यह एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है, 54 या 55 देश हैं इसमें, और ज़ाहिर है कि हमें केवल समग्र नज़रिया ही मिल सकता है क्योंकि केंद्र में, दक्षिण में, उत्तर में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बहुत सारी विविधताएं हैं इसलिए हमें केवल एक अनुमान ही प्राप्त हो सकता है कि वहाँ क्या- क्या उपलब्ध है। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे पास अफ्रीका पर दो वरिष्ठ विद्वान हैं जिनका लंबा अनुभव रहा है और जिन्होंने भारत में अफ्रीकी अध्ययन में अपना योगदान दिया है, और वे अब चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले मैं डॉ. रुचिता बेरी को लगभग पांच मिनट तक बोलने और आज के विषय पर अपनी टिप्पणी देने के लिए आमंत्रित करूँगा और फिर इसके बाद स्वाभाविक रूप से मेज़बान, डॉ. निवेदिता अपने विचार व्यक्त करेंगीं। जी हाँ, अब आपकी बारी है।

रुचिता बेरी: धन्यवाद, राजदूत राजीव भाटिया जी और धन्यवाद, आईसीडब्ल्यूए (ICWA) मुझे अफ्रीका पर चर्चा के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और सामयिक विषय पर अपने विचार साझा करने हेतु आमंत्रित करने के लिए। यह बात कुछ समय से नई दिल्ली के विचार मंचों के बीच चर्चाओं में गायब थी, इसलिए इसके आयोजन पर बहुत- बहुत धन्यवाद। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने इस मुद्दे पर पहले ही काफी कुछ कवर कर लिया है। हमारे पास चार वक्ता थे जिन्होंने जेन ज़ी(Z) के नेतृत्व वाली डिजिटल अभिव्यक्तियों के अलग- अलग पहलुओं पर बात की, जो वास्तव में अफ्रीका में विरोध प्रदर्शनों के पैटर्न को बदल रही हैं, जैसा कि पहले होता था।

मैं कुछ बातें कहना चाहूँगी। पहली, जैसा कि राजदूत भाटिया आपने बताया- यह कोई ऐसी बात नहीं है जो केवल अफ्रीका तक सीमित है। यह ग्लोबल साउथ, एशिया, अफ्रीका में आम है। मैंने बीते कुछ सालों में लैटिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं देखा लेकिन एशिया और अफ्रीका में निश्चित रूप से ऐसे कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अफ्रीका के सभी इलाकों में एक बात बहुत आम है कि इसका कारण एक ही है और वह है युवाओं के लिए रुके हुए मौके, बढ़ती असमानता। सोशल मीडिया पर इस बारे में बहुत चर्चा हुई है कि कैसे अमीर लोग हेरफेर करके या गलत तरीके से पैसा जमा कर रहे हैं और आम लोग पीछे छूटते जा रहे हैं।

बढ़ती बेरोज़गारी और वृद्ध होता राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासकों और युवाओं के बीच पीढ़ी का अंतर, यह एक ऐसा कारक है जो बहुत आम हो चुका है और साथ ही वे सभी अपनी परेशानी बताने या युवाओं के बीच राजनीतिक समर्थन जुटाने के लिए अलग-अलग सोशल मीडिया हैंडल का प्रयोग करते हैं। ये ऐसे कारण थे जो आम थे, चाहे आप केन्या का मामला उठा लें, मोरक्को का या मेडागास्कर, युगांडा का, इन सभी जगहों पर यही आम कारक थे।

जैसा कि पहले बताया गया है, अफ्रीका में जनसांख्यिकी बताती है कि 70% आबादी 30 वर्ष से कम लोगों की है। इसलिए औसत उम्र लगभग 19 वर्ष है। आप उस पीढ़ीगत अंतर से कैसे निपटेंगे जहाँ 70% आबादी 30 वर्ष से कम लोगों की है, लेकिन इन देशों को चलाने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं? सोच और विचारों में भिन्नता है। दरअसल उन्हें जो चाहिए, वह पाने में उन्हें ही बहुत नुकसान हो रहा है, चाहे वह नौकरी हो या बेहतर ज़िंदगी की उम्मीद। यदि आप इन कुछ देशों में हुए विरोध प्रदर्शनों को देखें, जैसे केन्या में, तो यह वास्तव में कर (टैक्स) की वजह से हुआ था, जिससे लोगों के लिए रहना और भी महंगा हो जाएगा जिसकी वजह से विरोध प्रदर्शन हुए।

मेडागास्कर में, यह कुछ ऐसा था, मुझे लगता है कि यह खराब सरकारी सेवा या पानी और बिजली का मुद्दा था। मोरक्को के मामले में, स्वास्थ्य और शिक्षा कारण थे। लेकिन एक बात जो आम है वह यह है कि इन सभी विरोध प्रदर्शनों को सरकार ने दबा दिया। उन्होंने इन सभी विरोध प्रदर्शनों को दबा दिया और ज्यादातर मामलों में यह दमन हिंसक रहा। संख्याएं अलग- अलग हो सकती हैं। कुछ मामलों में, 40 लोग घायल या गिरफ्तार हुए या दूसरों में 60 या उससे अधिक, या केन्या में यह संख्या सैंकड़ों में थी। लेकिन ये इन विरोध प्रदर्शनों का हिंसक दमन था।

इसका मतलब है कि अभी के नेता, अफ्रीका के अभी के संभ्रांत वर्ग के लोग, युवाओं को कमान सौंपने के लिए तैयार नहीं हैं। वे इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि युवा समाज का एक ऐसा हिस्सा हैं जिनके साथ उन्हें बातचीत करने की ज़रूरत है। जब तक वे युवाओं से बात नहीं करेंगे, मेरे कहने का अर्थ है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 70% आबादी 30 वर्ष से कम उम्र वालों की है, इसलिए यदि आप भविष्य में टिकाऊ, स्थिर सरकार चाहते हैं तो आपको बातचीत करनी होगी। लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे राजनीतिक संभ्रांत लोग नज़रअंदाज़ कर रहे हैं।

दूसरी बात, मैं यह बताना चाहूँगी कि इन विरोध प्रदर्शनों में कुछ चुनौतियां हैं जो स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। प्रदर्शनकारी कहते हैं कि ठीक है, हमारा कोई नेता नहीं है और यह विरोध प्रदर्शन का एक सकारात्मक बिन्दु है। क्योंकि वे कहते हैं कि यदि कोई नेता नहीं है तो इसका मतलब है कि सरकार हमारे किसी भी नेता को अपने साथ मिलाकर विरोध प्रदर्शन को समाप्त नहीं कर सकती। यह उनका तर्क है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, यदि कोई नेता नहीं है तो जेन ज़ी (Z) प्रदर्शनकारियों के बीच कोई दिशा नहीं है। उनके पास कोई दीर्घकालिक विज़न नहीं है कि भविष्य में क्या करना होगा? अगर वर्तमान तरीके विफल हुए तो फिर क्या करेंगे?

यह सच है कि कुछ मामलों में, जैसे कि मेडागास्कर के मामले में जेन ज़ी (Z) के विरोध प्रदर्शन को एक सफलता के रूप में बताया गया है, कि इससे सरकार में परिवर्तन हुआ। लेकिन जैसा कि वक्ताओं ने बताया, सरकार में परिवर्तन का अर्थ था सेना ने सरकार पर कब्ज़ा कर लिया। वह व्यक्ति और प्रधानमंत्री एक बहुत ही अलोकप्रिय व्यापारी था। इसलिए मेडागास्कर के प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि सरकार ने हमारी क्रांति को हाईजैक कर लिया है। और हम नहीं चाहते कि हमारी क्रांति को भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट नेता हाईजैक कर लें। यही इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ उनकी मूल नाराज़गी है।

इसलिए, वे कहते हैं कि यह विरोध भविष्य में भी जारी रहेगा, शायद ज़मीनी स्तर पर। लेकिन यह जारी रहेगा। तो जब तक सरकारें और जेन ज़ी(Z) के प्रदर्शनकारी भविष्य में किसी तरह की बातचीत नहीं करते, यह विरोध खत्म नहीं होगा। मैंने केन्या, मोरक्को, मेडागास्कर में इन प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को भी पढ़ा है। वे कहते हैं कि हमें सच में सरकार का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन कम- से- कम सरकार को उन चिंताओं पर विचार करना चाहिए जिनके लिए हमने सच में आवाज़ बुलंद की है, जिन समाधानों को हम तलाश रहे हैं, वे मिलने चाहिए।

आखिर में, मुझे लगता है कि घाना के प्रोफेसर ने जो बात उठाई थी, कि केवल आर्थिक या सामाजिक मुद्दे ही जेन ज़ी (Z) को परेशान नहीं कर रहे हैं। सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी हैं जिनकी वजह से ये विरोध प्रदर्शन हुए हैं। जैसा कि पिछले वक्ता ने कहा, सरकारों ने जेन ज़ी(Z) के विरोध प्रदर्शनों को सुरक्षा का मुद्दा बना दिया है, बजाय इसके कि इसे एक राजनीतिक मुद्दा माना जाए, जो कि ध्यान देने वाली बहुत ही ज़रूरी बात है। यह अफ्रीका में भविष्य की स्थिरता और लोकतंत्र के भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत- बहुत धन्यवाद।

राजीव भाटिया: बहुत- बहुत धन्यवाद। बहुत स्पष्ट टिप्पणियाँ। मुझे वास्तव में इन पर अधिक विस्तार से बताने या टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अब जल्दी से डॉ. निवेदिता रे से उनकी विशेषज्ञ टिप्पणियाँ देने का अनुरोध करूँगा। धन्यवाद।

निवेदिता रे: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे विचार में सभी वक्ताओं और पैनल के सदस्यों ने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। चर्चा में अंतिम वक्ता होने के नाते, संक्षेप में अपनी बातें कहना मुश्किल हो जाता है। मैं यह करती हूँ कि आप सभी ने जो बताया उसका एक सारांश प्रस्तुत करती हूँ और फिर बड़ी चर्चा के लिए प्रश्न उठाती हूँ। मैं यहाँ पांच मुद्दों पर बात करूँगी। मूल रूप से मेरी राय अधिक तुलनात्मक और थोड़ा अधिक अवधारणात्मक होगी।

मैं वहीं से अपनी बात शुरू करती हूँ जो अध्यक्ष महोदय ने शुरू में उठाया था। क्या अफ्रीका में हो रहे विरोध प्रदर्शन, जो हम अभी देख रहे हैं, कुछ बहुत नया है? जिसने भी अफ्रीकी अध्ययन किया है, और जब हम इस विशेष संवाद के बारे में विचार कर रहे थे, तब हमने सोचा कि हम भारत- अफ्रीका के बारे में बहुत बात कर रहे हैं लेकिन अब अफ्रीका में जो हो रहा है, उस पर सोच- विचार कर सकके हैं, जेन ज़ी (Z) का विरोध प्रदर्शन? क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ जिसने विरोध प्रदर्शनों पर बहुत काम किया है, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों के बारे में बताया।

मैं जो पहला मुद्दा उठाना चाहती हूँ, जो सवाल पूछना चाहती हूँ, वह यह है कि क्या अफ्रीका में जेन ज़ी (Z) का विरोध सच में नया है? जब आप जेन ज़ी (Z) विरोध प्रदर्शन कहते हैं तो यह युवाओं के नेतृत्व वाला विरोध प्रदर्शन होता है। युवाओं के नेतृत्व वाला विरोध प्रदर्शन, क्या यह नया है? मेरा तर्क है कि नहीं, यह नया नहीं है। और यह नया क्यों नहीं है, यदि आप अतीत पर नज़र डालें, चाहे आप उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों की बात करें, चाहे आप रंगभेद विरोधी आंदोलनों की बात करें, चाहे आप 1990 के दशक के लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों की बात करें, इन ज्यादातर आंदोलनों में युवाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था। सर ने तो दक्षिण अफ्रीका में काम किया है। यदि कोई अफ्रीकी विद्वान 1976 के सोवेटो विद्रोह के बारे में जानता होगा और इसे उच्च विद्यालय के छात्रों ने बंटू शिक्षा प्रणाली के खिलाफ आगे बढ़ाया था, जहाँ अफ्रीकी भाषा, अफ्रीकान्स, न कि डच भाषा, थोपी जा रही थी। कैसे उस सोवेटो विद्रोह ने दक्षिण अफ्रीका में इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया।

एक बार फिर, 1990 के दशक में भी, सबा- सबा आंदोलन, यदि किसी को केन्य के बारे में याद है, तो यह एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसने डेनियल अराप मोई के खिलाफ एकल- पार्टी शासन को समाप्त कर दिया था। वह गवर्नेंस के मुद्दों के बारे में बात कर रहे थे। यह एकल- पार्टी शासन से बहु- पार्टी शासन में बदल गया। अब, हाल ही में, 2011 में, एक बार फिर, सेनेगल में येने मारे आंदोलन हुआ, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं- 'हम तंग आ गए हैं'। वर्ष 2011 में एक बार फिर, यह एक संगठित युवा आंदोलन था, जो फिर से बिजली कटौती, बढ़ते भ्रष्टाचार के मुद्दों के बारे में था, जिसके कारण 2012 के चुनावों में सरकार गिर गई, और हम सबने देखा कि सत्ता में परिवर्तन हुआ।

इसी तरह, फीस कम होनी चाहिए, यदि आप दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानते हैं। फीस कम होनी चाहिए। यह 2015 में शुरू हुआ था। यह छात्रों का विरोध प्रदर्शन जो पूरे दक्षिण अफ्रीका में फैल गया था, जहाँ वे शिक्षा, उच्च शिक्षा और ट्यूशन फीस, बढ़ती हुई ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी को खत्म करने की मांग कर रहे थे। इसी तरह, भारत या एशिया के कुछ हिस्सों में, हमने युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलन देखे हैं। और हम भारत को भी कवर करते हैं, जेपी आंदोलन, या हांगकांग, श्रीलंका। वे सभी युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलन थे।

लेकिन मेरा कहना यह है कि यह अफ्रीका में नया नहीं है। लेकिन जो नया है, वह है लामबंदी का तरीका और रफ्तार। यही इसे नया बनाता है। और सबने इस बारे में बात की। उनकी टिप्पणियों में यह बात सामने आई। दो बातें जो हमने जानी। एक, पुराना विरोध प्रदर्शन, छात्रों के नेतृत्व वाला विरोध प्रदर्शन जो हमने देखा या संगठन के नेतृत्व वाला विरोध प्रदर्शन, वे ज्यादा संगठन-

केंद्रित थे, और जहाँ ऊपर से नीचे तक एक पदानुक्रमित मॉडल होता था। इसके मुकाबले, अब हम जो देखते हैं वह एक नेटवर्क-केंद्रित कार्रवाई है जिसके बारे में सबने बात की। संगठन- केंद्रित से नेटवर्क- केंद्रित।

फर्क विरोध की भावना में नहीं है। फर्क यह है कि, वास्तव में, कोई बिचौलिया नहीं है। पिछले युवा नेता, उन्होंने अपनी लड़ाई में एक करिश्माई नेता का साथ दिया था। लेकिन जेन ज़ी (Z) ने नेता को मार दिया है। वे बिना नेता के हैं। इसलिए किसी ने कहा था कि देश के लिए अपराधियों का सफाया करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं है। यह उस दूसरे मुद्दे पर आता है जिस पर मैं ज़ोर देना चाहती हूँ। एक बार फिर, दूसरा विकल्प, दोनों। पहले और अब युवाओं के नेतृत्व वाला विरोध प्रदर्शन। विचारधारा बनाम असल ज़िंदगी के अनुभव।

तो, सैद्धांतिक नज़रिए से यह सापेक्ष अभाव के सिद्धांत से बहुत हद तक मेल खाता है, यदि किसी को इसके बारे में पता हो। क्योंकि आज जेन ज़ी (Z) को जो चीज़ जोड़ती है, जिसके बारे में हम सबने बात की, वह है बढ़ती हुई आकांक्षाएं और रुके हुए मौके। तो यह पीढ़ी अधिक पढ़ी- लिखी है, मोबाइल से बहुत अधिक जुड़ी है, और विश्व भर की नवीनतम जानकारी रखती है। लेकिन यह पीढ़ी बिना नौकरी वाले विकास, सीमित अतिसंवेदनशीलता, छोटे होते कल्याण राज्य और संकट से संभ्रांत लोगों के अलग- थलग रहने के माहौल में बड़ी हो रही है। यही विचारधारा के बीच का अंतर है।

अब, यदि आप इन सभी विरोध प्रदर्शनों को देखें जिनके बारे में हमने बात की, चाहे वह केन्या हो या नाइज़ीरिया, या 2023 में श्रीलंका के बहुत करीब आना, ये सभी आर्थिक पतन की ओर ले जाते हैं। को सापेक्ष अभाव। लेकिन यहाँ जिस बात पर ज़ोर देना ज़रूरी है, वह यह है कि यहाँ अभाव भौतिक नहीं है। यहाँ अभाव डिजिटल रूप से बहुत अधिक दिखाई देता है और सोशल मीडिया इसे और अधिक प्रमुखता से दिखाता है, इन असमानताओं को उजागर करता है। यानि शासक और शासित। अफ्रीका और दुनिया। दुनिया बदल रही है। अफ्रीका संसाधन समृद्ध है लेकिन फिर भी उसे लूटा जा रहा है। इसलिए, यह लोगों के लिए भावनात्मक रूप से बहुत आवश्यक है। यह कोई अमूर्त बात नहीं है, जैसा कि जब हमने दूसरे विरोध प्रदर्शनों के बारे में बात की थी, मान लीजिए पूरे अफ्रीका से संबंधित विचारधारा के तौर पर, जो अधिक अमूर्त है, लेकिन यह अधिक तात्कालिक है।

तो यह तीसरे मुद्दे पर आता है जिस पर मैं ज़ोर देना चाहती हूँ, जिसके बारे में समीर और दूसरे वक्ता पहले ही बात कर चुके हैं, डिजिटल स्पेस। मुझे नहीं लगता कि डिजिटल स्पेस केवल साधन भर हैं। वे नए राजनीतिक अवसंरचना हैं। जहाँ हम देखते हैं, और जब हम बात करते हैं, कोई भी, जब आप विरोध प्रदर्शनों के बारे में बात करते हैं, तो यह इस बारे में होता है कि आप विरोध प्रदर्शन किस तरह से कर रहे हैं। आपको किसी संगठन तत्व की आवश्यकता होती है, कोई विचारधारा या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको जोड़े रखे। लेकिन वही बात, संगठन तत्व। तो मैंने सापेक्ष अभाव की बात की, कारकों की बात की लेकिन वे खुद से संगठित नहीं होते। किसी को यदि लोगों को इकट्ठा करना है तो वह डिजिटल स्पेस है। यहाँ, डिजिटल स्पेस में, आपके पास परंपरागत स्रोत नहीं होते बल्कि आपके गैर- परंपरागत स्रोत जैसे सोशल मीडिया, क्राउडफंडिंग, इन्फ्लुएंसर नेटवर्क, डिजिटल नैरेटिव, ये सभी इसी तरह के आंदोलन में प्रयोग होते हैं।

मैंने एक किताब पढ़ी थी, जिसमें किसी ने आज के तरीकों के बारे में लिखा है, जिसके बारे में हम डिजिटल विरोध प्रदर्शन आदि के बारे में बात कर रहे हैं। इसे अनुयोजक कार्रवाई बनाम सामूहिक कार्रवाई कहते हैं। सामूहिक कार्रवाई में पहले एक विचारधारा होती थी, जिसमें 'हम' होता था। 'हम' एक विचारधारा के रूप में बच गए। लेकिन आज, अनुयोजक कार्रवाई होती है। 'हम' जैसा कुछ नहीं है। 'मैं' हूँ। मैं इस विरोध प्रदर्शन में इसलिए हिस्सा ले रहा हूँ क्योंकि मैं किराया नहीं दे सकता। इसलिए वित्त बिल को खारिज करो। तो यहाँ 'मैं' कारक, यहाँ व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम इस तरह के समूह को देखते हैं। तो अनुयोजक बनाम सामूहिक तत्व, जहाँ 'मैं' बहुत ज़रूरी हो जाता है।

तीसरा, फिर से उसी अवधारणा पर आते हैं, नेटवर्क आंदोलन अवधारणा, जिसके बारे में सभी वक्ताओं ने किसी- न- किसी रूप में बात की है, उसकी खूबियां और कमियां। तो खूबियां क्या हैं? बिल्कुल सही। यह तेज़ी से अपनाया जा सकने वाला होता है। इसे जल्दी से बहुत बरे पैमाने पर फैलाया जा सकता है। यह सशक्त है। इन सब पर बातें हो चुकी हैं। लेकि फिर, कमियाँ भी तो हैं। आपके पास लामबंदी क्षमता बहुत अधिक है लेकिन संस्थायन बहुत कम। तो ये विरोध प्रदर्शन, आपको बहुत अधिक समन्वित और तेज़ी से बड़े पैमाने पर फैल जाने वाले और अनुकूलनीयता के साथ मिलेंगे। और इसका हिस्सा बनने के लिए प्रवेश का मार्ग बहुत सरल है।

लेकिन साथ ही, यदि आप साप्ताहिक देखें, यह साप्ताहिक संस्थायन है। और क्यों साप्ताहिक संस्थायन हैं, इसके बारे में दूसरे वक्ताओं ने पहले ही बता दिया है, क्योंकि यह नेता विहीन होता है। और जब आपका कोई नेता नहीं होता, तो आपके पास संवाद करने वाला कोई प्रतिनिधि नहीं होता। इसलिए विरोध की उर्जस्विता को किसी नीति सुधार में परिवर्तित करना कठिन होता है। यहाँ जिस बात पर ज़ोर दिया जाना है, वह यह है कि आंदोलन असरदार तरीके से स्थिति को खराब कर सकते हैं। लेकिन संवाद करने या उस गति को दीर्घकालिक सुधार में बदलने का संघर्ष एक चुनौती है।

तो यदि आप सामाजिक अभियान के नज़रिए से देखें तो इससे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल उठता है। वह सवाल है- क्या बिना नेता वाले आंदोलन उथल- पुथल को स्थिर राजनीतिक परिणामों में बदल सकते हैं? यही वह सवाल है जो हमें पूछना चाहिए। साधारण ही बात यह है कि जो आंदोलन संवाद नहीं कर सकता, वह केवल गड़बड़ी पैदा कर सकता है। इसलिए जेन ज़ी (Z) के विरोध प्रदर्शन सड़क से किसी संरचना या किसी संस्था में नहीं बदलते। इसलिए वे राष्ट्र के रुको और देखो नीति वाले रवैये का जोखिम उठाते हैं। इसलिए राष्ट्र के पास सड़कों के प्रदर्शन की तुलना में अधिक समय होता है।

तो समस्या यहीं है, जब किसी ने कहा कि यह सफल क्यों नहीं है। इतना सब कुछ कहने के बाद, जब इन विरोध प्रदर्शनों के परिणाम की बात आती है तो मैं इस बार पर ज़ोर देना चाहूँगी कि जेन ज़ी (Z) के विरोध प्रदर्शन हमेशा सरकारों को नहीं गिरा सकते, हमेशा तत्काल नीति में परिवर्तन नहीं ला सकते। लेकिन वे निश्चित रूप से जो करते हैं, वह है वे राजनीतिक संवाद को फिर से परिभाषित करने का काम। लेकिन वे राजनीतिक संवाद को नया रूप देना ज़रूर सुनिश्चित करते हैं। वे पुराने संभ्रांत श्रेणी को गैर- कानूनी ठहराते हैं। वे इस बात को नया आकार देते हैं कि राजनीति में क्या संभव माना जाता है। इसलिए मैं कहूँगी कि उनका प्रभाव संस्थागत से अधिक निर्देशात्मक होगा।

निष्कर्षतः, मैं यह कहना चाहूँगी कि अफ्रीका में जेन ज़ी (Z) के विरोध प्रदर्शनों को एक अलग घटना के रूप में नहीं बल्कि एक वैश्विक पीढ़ीगत रुझान के हिस्से के रूप में समझा जाना चाहिए, जो, मैंने जिस सापेक्ष अभाव की बात की, उससे बना है, जो असमानताएं हम देखते हैं, उनमें जो अंतर है, उसे निश्चित रूप से संसाधनों के संघटन के नए तरीकों यानी डिजिटल स्पेस ने संभव बनाया है और इसे नेटवर्क आंदोलनों के माध्यम से जाहिर किया जाता है, जो नेता विहीन हैं, जो अनुप्रस्थ हैं, पहले ही तरह पदानुक्रमित नहीं। इसलिए वे क्रांतिकारी शक्ति के रूप में कम काम करते हैं। लेकिन वे निश्चित रूप से संकेत देते हैं और मैं कहूँगी कि यह समझने के लिए एक नैदानिक साधन भी है कि यह कहाँ दिखता है कि राष्ट्र वास्तव में नई पीढ़ी की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम हो रहे हैं।

चाहे वह केन्या का अनुभव हो, नाइजीरिया का या मोरक्को का अनुभव हो। मैंने जो देका है वह यह है कि जेन ज़ी(Z) पुलिस से अधिक गरीबी से डरती है। मूल सवाल जिसके साथ मैं अपनी प्रस्तुति को समाप्त करूँगी, वह अफ्रीकी और केवल अफ्रीकी ही नहीं बल्कि एशियाई देशों के लिए भी है कि, क्या जेन ज़ी(Z) लामबंद होती रहेगी, बल्कि क्या राजनीतिक व्यवस्था इन परिवर्तनों को

किसी लोकतांत्रिक विचार में बदलने के लिए तेज़ी से खुद को ढाल पाएंगे, या इसे बार- बार होने वाली अस्थिरता में बदल देंगे। धन्यवाद।

राजीव भाटिया: बहुत- बहुत धन्यवाद। सारांश बहुत ही शानदार था। मेरा काम थोड़ा कम कर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने भविष्य में झांका, और आप इस नतीजे पर पहुँची कि, बिल्कुल सही, डिजिटल विरोध एक प्रकार का राजनीतिक आंदोलन है जिसे हम ग्लोबल साउथ, विशेष रूप से अफ्रीका में देख रहे हैं। यह अभी- अभी शुरू हो रहा है। यह क्या बदलाव लाएगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन स्पष्ट है, इसकी अपनी खूबियां हैं और कमियां भी हैं।

इस चरण में, दोस्तों, मुझे पता है हम समय- सीमा को पार कर चुके हैं लेकिन विषय बहुत ही दिलचस्प था। अपनी लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार, मैं आप सभी के मन में उठ रहे सवालों मे से कुछ का जवाब दिलवाना चाहूँगा। हमारे पास कुछ मिनटों का समय शेष है। हम प्रश्नोत्तर सत्र रख सकते हैं। सबसे पहले सवाल पूछने का मौका मैं उन्हें देना चाहूँगा जिन्होंने इस विषय पर चर्चा का सोचा था। नंदिनी, आप शुरू करें।

नंदिनी खंडेलवाल: पैनल के सदस्यों, बहुत ही बारीक टिप्पणियों के लिए धन्यवाद। चूंकि हमारी बातचीत जेन ज़ी (Z)- नीत विरोध प्रदर्शन से इतर अफ्रीका में शासन के बड़े मुद्दों पर चली गई, इसलिए मेरे पास करने को एक टिप्पणी और पूछने को एक सवाल है। जैसे, मेडागास्कर में हमने कमज़ोर शासन और संभ्रांत लोगों में फूट देखी, जिसके कारण सेना ने सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया लेकिन दूसरी ओर तंजानिया नाम का एक देश है, जहाँ हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन वहाँ सरकार और सेना के बीच भी गठबंधन था, जिसने विरोध को दबाने में मदद की और वे आज भी विरोध को कुचलने में लगे हैं।

इससे यह पता चलता है कि जेन ज़ी (Z) में बड़े मुद्दों को सामने लाने और उन्हें बढ़ाने की क्षमता है, लेकिन वे यह तय नहीं करते कि सरकारें गिरेंगी या बनी रहेंगी। यह कौन तय करता है कि राजनीतिक नतीजे असल में ये संभ्रांत लोग तय करते हैं? वास्तव में, संभ्रांतों की एकता। यदि संभ्रांतों की एकता ही आखिरकार परिणाम तय करती है तो हम इन संभ्रांतों के कब्ज़े से आगे कैसे बढ़ें ताकि जेन ज़ी (Z) का विरोध लंबे समय तक चल सके और असली नतीजे मिल सकें? धन्यवाद।

राजीव भाटिया: अच्छा सवाल है। अभिषेक, आप पास ही में बैठे हैं। आप ही इसका जवाब क्यों नहीं दे देते? चलो, इसे खत्म करते हैं। नहीं, नहीं, आप दो पैनल के सदस्य हैं। क्या आप जवाब देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते तो मैं समीर का रुख करूँगा। हाँ, समीर, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए।

समीर भट्टाचार्य: मुझे लगता है कि हमें केवल संभ्रांतों पर ही विचार नहीं करना चाहिए। मेरे विचार से संस्थानों का भी अंतर है। उदाहरण के लिए, मेडागास्कर एक बहुत गरीब देश है। उसके संस्थान विफल हो रहे हैं। उसकी तुलना में, तंजानिया के संस्थान अधिक स्थिर हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने जो किया वह सही है, लेकिन सरकार के पास कुछ ऐसे संस्थान हैं जिन पर वह विश्वास कर सकती है। जैसे, केन्या में, जब छात्र विरोध करते हैं, तो वित्त बिल के लिए छात्रों ने विरोध किया और युवाओं ने विरोध किया। कुछ संस्थाएं थीं। लोगों में अभी भी कुछ संस्थाओं, जैसे- पुलिस, सेना- के लिए सम्मान है।

मेडागास्कर में, मैं कहूँगा कि यह क्रांति की आड़ में एक तख्तापलट था। लेकिन यदि आप इन स्थानीय लोगों से पूछेंगे, तो वे कहेंगे, नहीं, नहीं, हम खुश हैं क्योंकि हम सरकार से ज्यादा सेना पर विश्वास करते हैं। जिसका अर्थ है कि सैन्य संस्था एक विश्वास का कारक थी। सैन्य संस्था के प्रति एक विश्वास का कारक था। मुझे लगता है कि यदि संस्थाएं मजबूत होती हैं, तो उन देशों में कभी- कभी बदलाव लाना अधिक मुश्किल होता है। फिर मैन ने यह भी कहा कि यह विरोध, भले ही हमें इसे सामान्य

मूल्यों के लिए मानना पड़े, भले ही तुरंत कोई बदलाव नहीं हुआ, तुरंत कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कम- से- कम कुछ बाधा तो पड़ी, कम- से- कम लोगों की राय सुनी तो गई।

राजीव भाटिया: देखिए, यह हमें अफ्रीका में लोकतंत्र की चुनौती के जड़ तक ले जाता है। मेरे विचार से, हमने जो पढ़ा और देखा है, वह लोकतंत्र की गिरावट को दिखाता है। इसमें एक विरोधाभास है। युवा असंतुष्ट और नाखुश हैं, उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का नया तरीका मिल गया है। लेकिन असल दुनिया में, शायद राजनीतिक दल कमज़ोर हैं, एनजीओ व्यवस्था कमज़ोर है, मीडिया अशक्त है, आर्थिक समस्याएं बहुत अधिक हैं और इसकी वजह से ही नाखुशी है, जिनके बारे में सार्वजनिक रूप से आवाज़ उठाई जाती है, वह राजनीतिक सुधार में नहीं बदल पाती। मैं यही समझ पाया हूँ लेकिन फिर से, मैं इस बात पर ज़ोर दूंगा कि ये शुरुआती अनुमान भर हैं। आप अभी अंतिम फैसला करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि आपके पास अभी पूरी जानकारी नहीं है। क्या कोई और सवाल पूछना चाहेगा? मुझे लगता है कि मैं यहाँ बैठी महिला को मौका देना चाहूँगा और मुझे लगता है कि घाना से आए हमारे दोस्तों को मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हम दो या तीन सवाल लेंगे। आप अपना सवाल पूछिए और फिर हम आपके पास आएंगे।

सुगंधि जे.: आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुगंधि, परिषद में शोध विश्लेषक हूँ। मेरा सवाल डॉ. भट्टाचार्य से हैं। जैसा कि हमने कई अफ्रीकी देशों में देखा है कि डिजिटल सक्रियता पर सरकारी दमन जारी है क्या आपको लगता है कि यह कदम अफ्रीकी युवाओं को विरोध के हिंसक तरीकों को अपनाने को मज़बूर कर सकता है, जैसा हमने मेडागास्कर विरोध प्रदर्शन में देखा था? धन्यवाद।

राजीव भाटिया: मुझे लगता है कि आपको थोड़ा रुकना चाहिए। मैं घाना से आए प्रतिभागियों से सवाल पूछना पसंद करूंगा। जी हाँ, अपना सवाल पूछें।

अज्ञात प्रतिभागी: पैनल के सदस्यों और कक्ष में उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। मुझे मौका देने के लिए बहुत- बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल डॉ. गॉडफ्रेड सर से है। सर, जैसा कि आपने कहा कि अफ्रीकी महाद्वीप एक तरह से युवा महाद्वीप है, क्योंकि वहाँ 30 साल से कम उम्र के लोगों की आबादी बहुत अधिक है और औसत उम्र 19 वर्ष है। सर, हमने हाल ही में एआई (AI) के क्षेत्र में बूम देखा है। तो सर, अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी सरकारें अफ्रीकियों के बीच बढ़ते कट्टरपंथ से किस प्रकार निपट रही हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस और फिर साहेल प्रोविंस जैसे आतंकवादी संगठन अपनी विचारधाराओं एवं प्रचार के लिए एआई का प्रयोग कर रहे हैं। धन्यवाद।

राजीव भाटिया: अच्छी बात है, मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल नया पहलू सामने रख दिया है, लेकिन मैं डॉ. गॉडफ्रेड का रुख करूँगा। हो सकता है कि वह आपकी इच्छानुसार दोनों ही सवालों का जवाब देना चाहें। आपकी बारी प्रोफेसर।

गॉगफ्रेड बोनाह नकानसाह: सवाल पूछने के लिए बहुत- बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा कि शासन का समर्थन करने के लिए एआई का प्रयोग करने के मामले में अफ्रीकी संघ बहुत पीछे है। यह एक बहुत ही नौकरशाही संस्था है, और केवल अफ्रीकी संघ ही नहीं। ईसीओडब्ल्यूएएस (ECOWAS), एसएडीसी (SADC) जैसे क्षेत्रीय संगठन भी हैं। वे बहुत नौकरशाही हैं, और इसी कारण उन्हें वर्तमान रुझानों के साथ तालमेल बैठाने में बहुत समय लगता है।

दूसरी तरफ, ये आतंकवादी समूह तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और डिजिटल क्रांति को हम देख रहे हैं, उसके साथ- साथ वे भी बदल रहे हैं। इसलिए, आतंकवाद या हिंसक उग्रवाद के प्रति अफ्रीकी संघ की वर्तमान प्रतिक्रिया, विशेषरूप से साहेल और दूसरे स्थानों पर, उतना असरदार नहीं रहा है क्योंकि तकनीक के मामले में संघ ने एआई के प्रयोग पर अपने दिशानिर्देशों और स्थिति के मामले में कोई विशेष छलांग या महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की है। सुरक्षा के क्षेत्र में यह एक चुनौती है और इसी वजह से, अलग-

अलग देश हिंसक उग्रवाद के खिलाफ समाधान लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें एआई और ड्रोन एवं दूसरे उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है जिनका प्रयोग इस चुनौती से निपटने के लिए किया जा सकता है। अफ्रीका के क्षेत्र में अभी यही स्थिति दिख रही है।

राजीव भाटिया: बहुत- बहुत धन्यवाद। अब हम सवालों के आखिरी दौर में हैं। कृपया अपना सवाल पूछें। इनके बाद मैं आपसे सवाल पूछने आऊंगा और फिर एक और प्रश्न लिया जाएगा, शायद इस तरफ से। कृपया पूछिए।

ताहिना रासामोएलिना: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं मेडागास्कर दूतावास से ताहिना हूँ। पैनल चर्चा में इस विषय को शामिल करने के लिए आईसीडब्ल्यूए का धन्यवाद। हम जैसे लोगों, जिन्होंने मेडागास्कर में चल रहे आंदोलन को देखा है, के लिए, यह बहुत ही जानकारी पूर्ण है। मैं जानना चाहती थी कि मेरे देश में जो हो रहा है उसके बारे में भारत क्या सोचता है? मैं इस चर्चा को अधिक विचारपूर्ण बनाने के लिए मेडागास्कर के लिए प्रवासियों की भूमिका के बारे में बताना चाहूँगी। दूसरे देशों के बारे में तो मैं नहीं बता सकती लेकिन मेडागास्कर के लिए हमारे 200,000 मालागासी लोग दूसरे देशों में रहते हैं जो वहाँ से करीब 380 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि मेडागास्कर में अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। इस आंदोलन में, प्रवासियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2015 से, हमने मेडागास्कर में प्रवासियों को एक मंच देना शुरू किया।

उदाहरण के लिए, हमने विदेश मंत्रालय में एक ऐसा विभाग बनाया है जो प्रवासियों का प्रभारी है और धीरे- धीरे इससे मेडागास्कर के लिए एक स्पष्ट प्रतिबद्धता एवं स्पष्ट प्रक्रिया देखने को मिली। इस आंदोलन में, प्रवासियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसने अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में मदद की है। आपने ख़बरों में देखा होगा कि एक दिन हम न्यूयॉर्क टाइम्स और फ्रेंच पत्रिका की सुर्खियों में थे। इसलिए मेडागास्कर के लिए प्रवासी विशेष रूप से बड़ी भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2019 से, पूर्व राष्ट्रपति के समय से ही प्रवासी सरकार का हिस्सा बनना शुरू हो गए थे और अब धीरे- धीरे प्रवासी अहम भूमिका निभाते नज़र आ रहे हैं। धन्यवाद।

राजीव भाटिया: बहुत- बहुत धन्यवाद। आपकी टिप्पणी का शुक्रिया। जी हाँ, आप अपना सवाल पूछें।

दीपक: आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम दीपक है और मेरा सवाल डॉ. रुचिता बेरी मैम से है। मैम, आपने आंदोलनों के राजनीतिकरण के बजाय सुरक्षाकरण के विषय पर बात की। क्या आप जेन ज़ी (Z) आंदोलनों में बाहरी प्रभावों से डिजिटल सीमाओं की रक्षा करने की भूमिका देखती हैं, जो दूसरे देशों या गैर- सरकारी संगठनों में हो सकते हैं? क्या हमें बाहरी कारकों के प्रभाव से डिजिटल सीमाओं को बचाने की ज़रूरत है?

राजीव भाटिया: धन्यवाद। इस तरफ से एक आखिरी सवाल। जी हाँ, आप अपना सवाल पूछें।

प्रिया: सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रिया है। मेरा सवाल यह है कि क्या जेन ज़ी (Z) नीत विरोध प्रदर्शन रवांडा नरसंहार जैसे अलग- अलग जातीय संघर्षों से दूर होकर पूरे अफ्रीकी पहचान को वापस दिला सकता है?

राजीव भाटिया: टिप्पणियों और सवालों का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि मैं पैनल के हर एक सदस्य को एक- एक मिनट का समय दूं और हम उस तरफ से शुरू करें। आप पैनल का हिस्सा है, आप अपने गहन अवलोकन के अलावा एक मिनट में कुछ कहना चाहेंगीं, आप शुरू कर सकती हैं।

निवेदिता रे: मेरे पास पूछने को सीधा सवाल तो नहीं है लेकिन जो सवाल नंदिनी ने पूछा, हमने विरोध प्रदर्शन में होने वाले बदलावों पर बात नहीं की। जब मैं मेडागास्कर और तंजानिया में विरोध प्रदर्शन देखती हूँ, तो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है,

विशेषरूप से पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में विरोध प्रदर्शन को देखती हूँ तब, ये प्रदर्शन अधिकांशतः शासन के मुद्दों के बारे में हैं और जब मैं फ्रेंच भाषी अफ्रीका, मेडागास्कर को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ किसी तरह का बाहरी प्रभाव है, जहाँ सेना का कब्ज़ा करना एक महत्वपूर्ण बात है जो दूसरी जगहों पर नहीं होता है और फिर से बाहरी प्रभाव, बाहरी पक्षों और संप्रभुता का मुद्दा आता है जो ज़्यादातर फ्रेंच भाषी अफ्रीका में देखने को मिलता है।

यहीं आप देखते हैं कि जहाँ एक अच्छी सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था हो, बहुत मज़बूत, वे साथ मिलकर विरोध करते हैं, विरोध का जवाब साथ मिल कर देते हैं, लेकिन मेडागास्कर में ऐसा नहीं दिखता, यह एक फ्रेंच भाषी अफ्रीकी देश है। हो सकता है कि मैं गलत होऊं लेकिन घटनाओं पर नज़र डालने का यह मेरा तरीका है कि एक फ्रेंच भाषी अफ्रीकी देश और अंग्रेजी भाषी अफ्रीकी देश कैसे अलग होते हैं।

राजीव भाटिया: धन्यवाद।

रुचिता बेरी: धन्यवाद। मुझे लगता है कि मुझसे एक सीधा- सीधा सवाल पूछा गया है, यह डिजिटल सीमाओं के बारे में है। अब जब कई देश इस पूरे जेन ज़ी (Z) विरोध प्रदर्शन को सुरक्षा के नज़रिए से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिस पर राजनीतिक नेतृत्व को ध्यान देना होगा। डिजिटल फील्ड पर निश्चित रूप से अधिक पाबंदियां हैं, डिजिटल सीमाओं के बारे में निश्चित रूप से फिर से सोचा जा रहा है और उन पर ध्यन दिया जा रहा है, अलग- अलग प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण के मामले में डिजिटल पाबंदियां लगाई जा रही हैं। पहले यह केवल आतंकवादियों और दूसरे असामाजिक तत्वों से जुड़ा था, लेकिन जेन ज़ी (Z) कारक और जेन ज़ी (Z) विरोध प्रदर्शनों में वृद्धि की वजह से, मुझे लगता है कि सरकारें डिजिटल सीमाओं को बहुत सावधानी से नियंत्रित करने पर ध्यान दे रही हैं।

विशेष रूप से इसलिए क्योंकि इनमें से कई प्रदर्शनकारियों ने दूसेर देशों में हुए विरोध प्रदरशनों के उदाहरण देखे हैं। खासकर मेडागास्कर में, मुझे ऐसी रिपोर्टें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि इनमें से कई प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के मामले को एक उदाहरण के रूप में देखा, एक ऐसी योजना के तौर पर कि उन्होंने मेडागास्कर में अपने विरोध प्रदर्शन कैसे किए। साथ ही, प्रवासी की अहम भूमिका निभाने का सवाल भी है जिसे यहाँ मेडागास्कर दूतावास के प्रतिनिधि ने बताया है। लेकिन मुझे लगता है कि यह भी एक ऐसा कारक है जो कई देसों में सामने आ रहा है, कि प्रवासी धीरे- धीरे अलग- अलग देशों में राजनीतिक परिवर्तन का एक माध्यम बनते जा रहे हैं, चाहे वह जेन ज़ी (Z) आंदोलन को समर्थन करके हो या वैकल्पिक राजनीतिक दलों का समर्थन करने की परंपरागत भूमिका निभाकर हो। यह देखना अभी बाकी है।

राजीव भाटिया: धन्यवाद। बहुत- बहुत धन्यवाद। समीर?

समीर भट्टाचार्य: मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मूल रूप से, यह हिंसक होगा या नहीं, देखिए, इनमें से कुछ विरोध प्रदर्शन पहले ही हिंसक रूप ले चुके हैं। कुछ जगहों पर कई लोग मारे गए। छह लोग मारे गए। कुछ घायल हैं। कुछ जेल में हैं। तो यह हिंसक होगा या नहीं, यह सवाल ही नहीं उठता क्योंकि यह पहले ही हिंसक हो चुका है। लेकिन ये सरकारें, बहुत चालाक हैं। मैं एक लेख पढ़ रहा था। अच्छा हुआ कि हम युगांडा के बारे में बात कर रहे थे, वह व्यक्ति लापता है। युगांडा की आबादी की औसत उम्र 30 वर्ष है। और युगांडा के राष्ट्रपति बीते 40 वर्षों से अपने पद पर बने हुए हैं। इसलिए ज्यादातर लोग, जो आज मतदान कर रहे हैं, वे उस समय पैदा भी नहीं हुए थे जब युगांडा के राष्ट्रपति ने पदभार ग्रहण किया था।

मैं एक लेख पढ़ रहा था कि यह राष्ट्रपति हर साल कैसे जीत जाते हैं। तो इन लोगों की एक अच्छी बात यह है कि वे लोगों की नब्ज़ पहचानते हैं। इसलिए वे हमेशा, आखिरी पल में, कुछ दिखावटी बदलाव कर देते हैं, कुछ करते हैं, कुछ सपने दिखाते हैं और

फिर लोगों को शांत कर देते हैं लेकिन फिर जेन ज़ी (Z), उनकी चुनौतियां वास्तविक हैं, रीयल- टाइम की चुनौतियाँ हैं। जब तक इन चुनौतियों का समाधान नहीं किया जाएगा, वे विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। यदि उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई, तो यह विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाएगा। इसलिए मैं समाधान के बारे में सोचता हूँ, मैं बस इतना कहूँगा कि अफ्रीका की सभी सरकारों को कोई ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए जिसमें इन युवाओं की आवाज़ को सुना जा सके। इसका मतलब यह नहीं है कि युवाओं को राष्ट्रपति या मंत्री बनाना है, जो असल में हुआ भी है। सेनेगल में राष्ट्रपति बहुत कम उम्र के हैं, उनकी उम्र लगभग 44 वर्ष है। लेकिन कम- से- कम कोई ऐसी व्यवस्था हो जहाँ वे अपनी बात कह सकें, अपनी आवाज़ उठा सकें।

राजीव भाटिया: धन्यवाद।

अभिषेक मिश्रा: क्या जेन ज़ी (Z) के विरोध प्रदर्शन, क्या वे कोई पूरे अफ्रीका में पहचान को सामने ला सकते हैं, इस सवाल के जवाब में मेरा मानना है कि कोई भी पूरे- अफ्रीका में पहचान लाना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि, हमें यकीन है कि डिजिटल साधन विरोध प्रदर्शन के लिए साधन के रूप में बहुत अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन जब विरोध प्रदर्शन की बात आती है तो हमें अलग- अलग क्षेत्रीय विभिन्नताओं का भी ध्यान रखना होगा। जैसे, छोटे द्वीप विकासशील देशों की समस्याएं अलग होंगी। पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के देश ज्यादातर विरोध, यानि शासन और सामाजिक मुद्दों के विरोध पर ध्यान देते हैं।

जबकि पश्चिम की तरफ या साहेलियन तरफ, यह ज्यादातर इस सवाल पर होता है कि, मेरे विचार में राजदूत भाटिया ने शुरुआत में पूछा था, क्या विरोध प्रदर्शन क्या उनका औपनिवेशिक युग के विरोध प्रदर्शनों से कोई लेना- देना है? मुझे लगता है कि महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में, उनकी ऐतिहासिक शिकायतें उनके औपनिवेशिक अनुभवों से अधिक जुड़ी हुई हैं। उनका बाहरी प्रभाव भी बहुत अधिक शामिल है। इसलिए कुल मिलाकर, पूरे अफ्रीका में पहचान बनाना मुश्किल होगा। लेकिन विरोध प्रदर्शन करने के लिए डिजिटल साधन का प्रयोग करना, यह बेशक प्रचलित और न्यू नॉर्मल है।

राजीव भाटिया: पैनल के सदस्यों आप सभी का बहुत- बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी चर्चा की। चाय के लिए सम्मेलन कक्ष की ओर प्रस्थान करने से पहले मैं कुछ बातों कहना चाहता था। अफ्रीका को बड़े स्तर पर देखना और विश्व में, विशेष रूप से भारत में जो हो रहा है, उसे देखते हुए, मैं यह कहना चाहूँगा कि अफ्रीका में जेन ज़ी (Z) पीढ़ी का काम असल में अफ्रीका के लिए एक अच्छी ख़बर है क्योंकि इसका उद्देश्य लोकतंत्र को मज़बूत करना है। इसका उद्देश्य शासन को बेहतर बनाना है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि युवाओं और उनके विचारों को समाज और सरकार द्वार सुना जाए।

ऐसा मुख्य रूप से अफ्रीका के कुछ देशों में शासन व्यवस्था की खामियों की वजह से हो रहा है। राजनीतिक दल कमज़ोर हैं। मीडिया को अक्सर पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलती। स्वयंसेवी संगठन ठीक से काम नहीं करते। विचारमंच शायद उतने शसक्त न हों। और इसलिए, युवा, विशेषरूप से जिन्होंने शायद अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें लगता है कि भविष्य अंधकारमय है। तो वे क्या करते हैं? वे अपनी निराशा ज़ाहिर करना शुरू कर देते हैं और फिर उसे अपने शयनकक्ष से निकालकर सड़कों पर ले आते हैं।

और मैं यह बताना चाहता था कि भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि अंतर बहुत अधिक है और मुझे बहुत खुशी है कि कम- से- कम एक अफ्रीकी विद्वान मुझे सुन रहे हैं। बात यह है कि यह एक ऐसा देश है जहाँ राजनीतिक व्यवस्था काम करती है। अधिकारी उत्तरदायी हैं। यहाँ राजनीतिक दलों की उपस्थिति हैं। मीडिया को पूरी आज़ादी है। यह किसी एक पक्ष या दूसरे पक्ष की तरफ हो सककी है लेकिन अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। विचार मंच मजबूत हो रहे हैं। स्वयंसेवी संगठन भी मज़बूत हैं। और इन सबसे ऊपर हमारी जेन ज़ी (Z) जिसकी औसत उम्र, जैसा कि आपने कहा, 19 साल है, कक्षा 12 की

परीक्षा देने के बाद विश्वविद्यालय में सीट पाने में व्यस्त हैं। वे राजनीतिक व्यवस्था में सुधार के लिए सड़कों पर नहीं उतर रहे क्योंकि ये काम दूसरे लोग कर रहे हैं।

तो मुझे लगता है कि भारत के लिए यह ज़रूरी है कि वह अफ्रीका के घटनाक्रम पर नज़र रखे, उसका अध्ययन और शोध करे, और मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम भारत- अफ्रीका संबंधों या अफ्रीका में चीन की भूमिका या अमेरिका ने अफ्रीका में क्या किया है या नहीं किया है, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल अफ्रीका के बारे में बारे में बात कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें अफ्रीकी लोगों के फ़ायदे के लिए यह भी बताना चाहिए कि अफ्रीकी महाद्वीप में ऐसा क्यों हो रहा है और भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो कुछ समानताएं हैं, एक- दूसरे को समझने की आपसी ज़रूरत है।

इसलिए, आखिर में, मुझे लगता है कि मैं आईसीडब्ल्यूए को एक सुझाव देना चाहूँगी। यहीं पर मत रुक जाइए। इसका विस्तार करिए। अफ्रीका आपका खास काम था, जब तक दूसरे लोग आकर इसे आपसे छीनने नहीं लगे। और जब आप अगली बार ऐसा कोई सम्मेलन करें तो सुनिश्चित करें कि उसमें अफ्रीकी प्रतिभागि अधिक हों। आप जेन ज़ी (Z)- नीत डिजिटल अभिव्यक्तियों पर बात कर रहे हैं, और तकनीक का अधिक- से- अधिक प्रयोग न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके पास अफ्रीका में विशेषज्ञों का बड़ा नेटवर्क है। उन्हें साथ लाइए। कम- से- कम उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए, जैसे चार भारतीय विशेषज्ञ और चार अफ्रीकी विशेषज्ञ। तभी हमारी बातचीत और भी अधिक सच्ची होगी। दोस्तों बहुत- बहुत धन्यवाद। आप आखिर तक हमारे साथ बने रहे। हमने खुशी- खुशी इसे करीब एक घंटे से अधिक समय तक चलाया। धन्यवाद।

नंदिनी खंडेलवाल: आईसीडब्ल्यूए की ओर से, मैं इस सामयिक विषय पर अपने अनमोल विचार साझा करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय और वक्ताओं का दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। परिषद में शोध निदेशक डॉ. निवेदिता रे को उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए मेरा विशेष धन्यवाद। मैं अपने सभी साथियों और दर्शकों को भी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। आईसीडब्ल्यूए के शोध कार्य, कार्यक्रमों, आउटरीच प्रोग्राम्स और प्रकाशनों के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट और एक्स, लिंक्डइन, यूट्यूब एवं फेसबुक के हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जाएं। एक बार फिर आप सभी का बहुत- बहुत धन्यवाद। कृपया उपकक्ष में जलपान के लिए आएं।